RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ..सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-04, अंक - 12 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरुवार 23 दिसम्बर 2021 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

अपनी पीढ़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीढ़ा न पहुंचाना, यही तपस्या का स्वरूप है।

संत तिरूवल्लुवर

बड़ा घोटाला: अध्यक्ष ने दिए जांच के आदेश, सीईओ को हटाने के निर्देश जारी

भोपाल।

मध्य प्रदेश में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है बुधवार को म.प्र. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने अपनी ही सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए। वही सीईओ को हटाने के निर्देश दिए गए है।

दरअसल, शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा अपनी ही सरकार से नाराज नजर आए और उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अधिकारियों पर जमकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह से सवाल करते हुए उन्होंने सिरोंज जनपद पंचायत में हितग्राहियों को दी गई रकम की जानकारी मांगी थी, इस पर श्रम मंत्री ने जवाब में बताया, एक वर्ष में सिरोंज जनपद पंचायत में 5 हजार 976 हितग्राहियों को 30 करोड़ 40 लाख की राशि दी गई, ऐसे में एक वर्ष में इतनी बड़ी राशि एक जनपद में खर्च होने को लेकर सवाल खड़े हो रहे विधायक उमाकांत शर्मा ने पूरे प्रदेश में जांच की मांग की है।

विधायक के सवाल के बाद मंत्री के जवाब पर विधान सभा अध्यक्ष गिरिश गौतम ने आपत्ति जताई और कहा कि, कोरोना काल में एक वर्ष के अंदर एक ही जनपद पंचायत में कैसे इतनी राशि स्वीकृत की गई।विधानसभा अध्यक्ष ने जनपद पंचायत सिरोंज में पुत्री विवाह के लिए स्वीकृत राशि पर जाँच करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद पंचायत सीईओ को हटाकर जाँच के निर्देश दिए है।

पंचायत चुनावः ओबीसी पर मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद श्रेय लेने की होड हुई शुरू

टल सकते हैं पंचायत चुनाव...!

भोपाल।

मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी के आरक्षण को लेकर बहस के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि, पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। सीएम ने कहा, इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी। इसे लेकर सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की है और मामले पर कानूनविदों के साथ भी मंथन किया। इस ऐलान के बाद मामले पर श्रेय लेने की रेस शुरू हो गई। सीएम के ऐलान के तुरंत बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर खुद की तारीफकर ली और पूरे श्रेय खुद को दे दिया।

कांग्रेस के संघर्ष की फिर हुई जीत

एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर इसे अपने संघर्ष की जीत करार दिया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस के संघर्ष की फिर जीत हुई, शिवराज सरकार ने गलती स्वीकारते हुए पंचायत चुनावों को ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराने की कांग्रेस की माँग स्वीकार कर ली है।

ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे पंचायत चुनाव

मामले पर कमलेश्वर पटेल ने कहा कि, कमलनाथ के दबाव में शिवराज सरकार झुकी है और ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं करने की मांग को स्वीकार किया। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में कांग्रेस पार्टी आज विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लेकर आई थी। कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि, पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण न कराए जाएं और मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए। कमलनाथ ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग के बाद यह घोषणा कर दी थी कि, बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होने चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने कांग्रेस की इस मांग के सामने समर्पण कर दिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में कमलनाथ की मांग स्वीकार कर लीं।

भाजपा का चरित्र ओबीसी विरोधी

कमलेश्वर पटेल ने कहा कि, अब सरकार ने कह दिया कि वो ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है और इस मामले में दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कमलनाथ ने दो दिन पहले कांग्रेसी विधायक दल की बैठक के बाद यह दोनों मागें सरकार के सामने रखी थी। मध्य प्रदेश सरकार के इस बयान के बाद यह बात स्पष्ट हो गई है कि, भारतीय जनता पार्टी अब तक लगातार झूठ बोल रही थी। भाजपा की रणनीति जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया में संवैधानिक कमियां छोड़कर चुनाव से बचने की थी। भाजपा का चरित्र शुरू से ही ओबीसी विरोधी है।

बिना ओबीसी आरक्षण चुनावों के पक्ष में नहीं

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं। राज्य के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि, राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति में ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव न कराए जाए।

भूपेंद्र सिंह ने कहा कि, सरकार के जो भी प्रयास है, जो भी कानूनी प्रयास किए जा रहे हैं, उसके परिणाम एक-दो दिन में सामने आएंगे। केंद्र सरकार के सहयोग पर भी विचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि, विधानसभा में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। आपने भी सुना ही होगा कि पांच बार कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर हाईकोर्ट में स्टे के लिए रिट लगाई। जब पांच बार जबलपुर से स्टे नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई। कांग्रेस की रिट पर सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों में जो ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण है, उस पर रोक लगाई है। हम लोगों ने सारे प्रकरणों के क्रमांक सहित तारीखें और सारे तथ्य हाउस में रखे हैं। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी है। कांग्रेस की वजह से ही सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विधिमंत्री के ध्यान में इस विषय को लाया गया है। सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पंचायत चुनाव में मिले।

उन्होंने कहा कि, हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी बात कैसे रख सकते हैं, और क्या रास्ते हो सकते हैं, सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिले और पंचायत चुनाव इस शर्त पर हो कि 27 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी को मिले।

राहुल गांधी के मॉब लिंचिंग वाले ट्वीट पर मचा बवाल

नई दिल्ली।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मॉब 'लिंचिंग' वाले ट्वीट पर वो घिरते नजर आ रहे हैं, उनके ट्वीट से एक नया राजनीतिक घमासान छिड़ गया। हाल ही में पंजाब सहित कुछ जगहों पर भीड़ के कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डालने की घटनाएं देखने को मिली थी। इस पर राहुल ने मंगलवार को पीएम मोदी पर कटाक्ष किया और कहा कि, वर्ष 2014 से पहले 'लिंचिंग' शब्द सुनने में भी नहीं आता था। उन्होंने 'थैंक्यू मोदी जी' हैशटैग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ये ट्वीट किया था, जिसके बाद से वे भाजपा के निशाने पर आ गए।

राहुल जी मे ज्ञान का अभाव- डॉ. मिश्रा

राहुल गांधी अब मध्य प्रदेश के गृहमंत्री के निशाने पर भी हैं। उनपर पलटवार करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा, 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के लोगों ने देश में मॉब लिंचिंग की शुरुआत की थी। तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले राहुल गांधी जी को चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में तो मॉब लिंचिंग दिखाई दे रही है, लेकिन केरल में नहीं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मारा गया। वहां एक-एक कार्यकर्ता को कई-कई घांव लगे थे, जो उन्हें नहीं दिख रहा। राहुल जी को ज्ञान का अभाव है। मॉब लिंचिंग की शुरूआत कश्मीर से हुई थी। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति हैं। इसी का परिणाम कांग्रेस झेल रही है और आगे भी भुगतेगी।

ऐसे शुरू हुआ मामला

रविवार को पंजाब के कपूरथला के निजामपुर गांव में एक गुरुद्वारे में सिख धर्म के 'निशान साहिब' का अनादर करने के आरोप में एक आदमी को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। इसके अलावा हाल ही में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कथित बेअदबी के चलते भीड़ ने एक अन्य व्यक्ति की पीट-पीट कर जान ले ली। राहुल ने लिंचिंग पर हिंदी और अंग्रेजी में ट्वीट कर ध्यान खींचने की कोशिश की। उस पर खूब लाइक, कॉमेंट आए और मामला चर्चा में आ गया। इसपर भाजपा की तरफ से आईटी टीम के प्रभारी अमित मालवीय मैदान में आए और राहुल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पलटवार किया। उन्होंने राजीव गांधी के एक चर्चित बयान को शेयर किया जिसमें वहो कह रहे हैं कि, जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है।

राहुल गांधी पर गृह मंत्री का कटाक्ष- राहुल को पता नही लिंचिग कि शुरूआत कहा से हुई

भोपाल। प्रदेश के गृह मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने लिंचिंग संबंधी राहुल गांधी के जवाब मे अल्प-ज्ञान को हास्यास्पद बताया है। गृह मंत्री ने कहा कि, शायद राहुल को पता नहीं है कि लिंचिंग की शुरुआत कश्मीर में हिंदुओं और देश में 1984 के दंगों में सिखों के कत्लेआम से हुई थी। देश मे हुए 84 के दंगों में तो कांग्रेसी ही शामिल थे, लेकिन यह सब उन्हें नहीं दिखता। उन्हें तो केवल एक वर्ग के साथ हुई घटनाए ही मॉब लिंचिंग दिखती है। लगता हैं कि कांग्रेस के युवराज एक बार फिर तुष्टिकरण की राजनीति पर ही अग्रसर है जिसने कांग्रेस को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है, और वे गर्त में ले जाकर ही छोड़ेंगे।

चाइनीज कंपनियां इनकम टैक्स विभाग के रडार पर

नई दिल्ली, एजेंसी।

देशभर में काम कर रही कई चाइनीज कंपनियां इनकम टैक्स विभाग के रडार पर हैं। इनकम टैक्स विभाग चाइनीज कंपनियों पर छापेमारी कर रहा है। जानकारी अनुसार, विभाग को इन कंपनियों को लेकर कई अनियमितताएं की शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों के बाद विभाग चाइनीज कंपनियों पर सोमवार से ही छापेमारी कर रहा है। आईटी विभाग दिल्ली-एनसीआर में चाइनीज कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। इन कंपनियों में ओप्पो मोबाइल कंपनी और उसके वेंडर भी शामिल हैं।

ओमिक्रोनः पीएम मोदी आज करेंगे समीक्षा बैठक

नई दिल्ली।

देश में कोरोना महामारी के नए वैरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में आ गए हैं। पीएम मोदी आज एक बड़ी समीक्षा बैठक करके देश में ओमिक्रोन की स्थिति का जायजा लेंगे। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे।

बता दें, देश में ओमिक्रोन मरीजों का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। यह वैरिएंट अब देश के 15 राज्यों में फैल चुका है। पीएम मोदी की यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब केंद्र ने राज्यों को अलर्ट पर रहने और संक्रमण रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है। केंद्र की इस चिट्ठी में जरूरत के मुताबिक नाइट कर्फ्यू लगाने और शादी, पार्टी, अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या सीमित करने का बात कही गई है।

भारत में कब लगेगा बूस्टर डोज

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल के मुताबिक, कोरोना संक्रमण हमेशा शुरुआती चरणों में हल्के लक्षणों के साथ आता है। हम देश में सामने आ रहे मामलों और पैटर्न में किसी भी बदलाव को बहुत सावधानी से देख रहे हैं। जहां तक बूस्टर डोज का सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में कहा है कि, जरूरत और समय के आधार पर वैज्ञानिक निर्णय लिया जाएगा।

वहीं आईएलबीएस दिल्ली के निदेशक डॉ. एसके सरीन का कहना है, बूस्टर डोज जरूरी है। जब आप किसी टीके की दो खुराकें लेते हैं तो आपका सुरक्षा स्तर, विशेष रूप से 3 से 6 महीने के बाद नीचे चला जाता है। तीसरी खुराक या बूस्टर हो तो गंभीर संक्रमण, अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम हो जाती है।

यु.पी. के बाद म.प्र. में होगी प्रियंका गांधी की एंट्री

भोपाल।

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी अखाड़ा सजने लगा है। कांग्रेस इस बार यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सियासी मैदान में उतर रही है। खास बात यह है कि, प्रियंका गांधी लगातार यूपी का दौरा कर रही है क्योंकि कांग्रेस एक दिग्गज नेता ने उन्हें मध्य प्रदेश आने का न्योताभी मिला है। यानि 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूपी की तरह एमपी के सियासी मैदान में भी उतर सकती है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस कमर कसकर मैदान में उतरी है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी यूपी में जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यूपी में सक्रिए होने वाले हैं, वह पार्टी लिए प्रचार करेंगे। हाल ही में उन्होंने लखनऊ का दौरा भी किया था।

कमलनाथ ने दिया न्योता

जब कमलनाथ से उनके उत्तर प्रदेश दौरे के लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि, वह कल लखनऊ गये थे, वहां गजब का उत्साह है, प्रियंका गांधी के यूपी में प्रचार करने से एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश से लबरेज है, ऐसे में मैंने प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश आने के लिए भी आमंत्रित किया है। हालांकि कमलनाथ ने यह नहीं बताया कि, प्रियंका गांधी कब मध्य प्रदेश आ सकती है।लेकिन उनके इस बयान के बाद प्रदेश के सियासी हलकों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी अब एमपी में भी सक्रिए हो सकती है।

2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस

दरअसल, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2023 में होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश बुलाए जाने की हलचल 2023 की तैयारी के हिसाब से एक बड़ा दांव माना जा रहा है। दरअसल, यूपी में प्रियंका गांधी की सक्रियता से कांग्रेस इस बार जोश से लबरेज नजर आ रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी को एमपी में भी सक्रिय किए जाने की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है।

हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं होगा जब प्रियंका गांधी एमपी में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाती हुई नजर आएगी, इससे पहले वह 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश आ चुकी है।

10वीं-12वीं की परीक्षाओ में हुआ बदलाव

भोपाल। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र एमपी बोर्ड के जरिए 10वीं या 12वीं के परीक्षा का टाइम टेबल डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि छात्रों की सुविधा के लिए यहां भी टाइम टेबल की प्रति उपलब्ध कराई जा रही है।

बता दे कि, एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा जहां 18 फरवरी 2022 से शुरू होगी। वही एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी 2022 से शुरू होगी। हालांकि कोरोना संक्रमण और ठंड को देखते हुए एमपी बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है, एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा सुबह 9 बजे की बजाए 10 बजे से आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक संचालित होगी। एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं बोर्ड प्रायोगिक परीक्षा में सामान्य रेगुलर छात्र के प्रैक्टिकल एग्जाम 12 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी 2022 के बीच संचालित होंगे। जबकि स्वाध्यीय छात्रों के प्रैक्टिकल एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च 2022 तक संचालित होंगे।

भाजपा की ओर से चुनाव लड़वाने वाला संगठन खुद उतरा मैदान में

जिला पंचायत, जनपद सदस्य और सरपंच पद के लिए संगठन के बड़े पदाधिकारी मैदान में

जमीन स्तर पर नहीं हुई कोई बैठक, प्रत्याशियों के चयन के लिए कार्यकर्ताओं से नहीं ली गई राय, भाजपा के बागियों के भरोसे कांग्रेस

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

न्यायालय में रोज़ चुनाव निरस्त होने के डर के साये के बीच त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की पहले दौर की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हैं। नामांकन प्रक्रिया से लेकर, फार्म की जाँच और नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी हैं। ग्राम पंचायत पंच से लेकर जिला पंचायत तक किन प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना है ये भी तय हो चुका है। चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ ही प्रचार-प्रासार में प्रत्याशी मैदान में उतरने को तैयार है, इस बीच मैदान में उतरे प्रत्याशीयो ने मतदाताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है।

नहीं मिलता पार्टी का सिम्बोल, अधिकृत प्रत्याशी की होती है घोषणा

पंचायत स्तरीय चुनाव में किसी भी राष्ट्रीय और स्थानीय पार्टी के चुनाव चिन्ह का उपयोग प्रत्याशी को नही दिया जाता है, ऐसे में राजनीतिक दल केवल चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशीयो को अधिकृत करती हैं, ताकि पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी का वोटर व्यक्तिगत प्रचार कर सके और पार्टी अधिकृत को वोट दे सके। स्थानीय स्तर पर भी मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होता है, जहॉ जमीनी स्तर पर बने संगठन की बड़े चुनाव से पहले अग्नि परीक्षा होती हैं।

चुनाव लड़वाने के लिए होती है संगठन की सरंचना

किसी भी पार्टी द्वारा संगठन की संरचना किसी भी चुनावों में पार्टी के लिए उचित प्रत्यासी का चयन करने और अधिकृत प्रत्याशी को विजय दिलाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन देश के सबसे बड़े संगठन वाली पार्टी का दावा करने वाली भाजपा का संगठन पार्टी की रीति-नीति को ताक में रखकर चुनाव मैदान में उतर गया। यहां पहले चरण में होने वाले जिला पंचायत और जनपद सदस्य सहित सरपंच पद पर भाजपा की और से जमीनी कार्यकर्ताओ को तवज्जो देने के बजाये संगठन के बड़े पदों पर बैठे नेता खुद ही मैदान में उतर गये, जिनके ऊपर संगठनात्मक रूप से पूरे क्षेत्र में भाजपा का परचम लहराने की जिम्मेदारी थी, वो खुद की सीट निकालने की जुगत में रहेंगे। मतलब स्वयं की जीत के लिए हर स्तर पर सेटिंग कर अपनी ही पार्टी से जुड़े अन्य प्रत्याशीयो का भट्टा बिठाने में भी कोई चूक नही करेगे।

पदाधिकारी ही कूद पड़े मैदान में, कार्यकर्ता उपेक्षित, संगठन की साख दाव पर

बात करे पेटलावद विकास खण्ड की तो 77 पंचायतो में बटे इस विकास खण्ड में 03 जिला पंचायत और 25 जनपद सदस्यों के चुनाव होने हैं, जिला पंचायत के भाजपा द्वारा तीनो प्रत्याशियों को अधिकृत किया गया जो संगठन के महत्त्वपूर्ण पद पर है। क्षेत्र क्रमांक 12 से भाजपा की और खुद रायपुरिया मण्डल के मंडल अध्यक्ष शांतिलाल मुणिया मैदान में है, यहाँ भाजपा को कोई दूसरा चेहरा मिला ही नही। क्षेत्र क्रमांक 13 से भाजपा ने संगठन के जिला महामंत्री कृष्णपाल सिंह गंगाखेड़ी पर दाव लगाया, जबकि यहाँ इस सीट से कई युवा चेहरे मैदान में उतारे जा सकते थे, लेकिन संगठन से लेकर सांसद प्रतिनिधि के पद पर कब्जा करने वाले नेताजी की भूख यहाँ भी शांत नही हुई और कई दावेदार युवाओं और अनुभवी नेताओ को कुचल खुद ही मैदान में उतर गए हैं, जबकि जिला महामंत्री जैसे महत्त्वपूर्ण पद पर रह कर विकास खण्ड में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के प्रचार से लेकर चुनाव लड़ने की पूरी रचना की जिम्मेदारी उठाने के बजाए संगठन की मुख्य जवाबदेही को ताक मे रख खुद ही मैदान में उतर गए।

ऐसे ही कुछ हाल क्षेत्र क्रमांक 14 के भी है यहां से भाजपा ने अजजा मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष नीलेश मीणा को मैदान में उतारा है, हालांकि नीलेश मीणा इस क्षेत्र से एक बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, इसलिए भाजपा यहां कोई नया चेहरा नही ला सकी, यहाँ कांग्रेस की और से विधायक वालसिंह मैडा के पुत्र विक्रम मैडा मैदान मे खडे हुए है इसलिए यहाँ का चुनाव राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो गया है। जिला पंचायत ही नही जनपद सदस्य में भी भाजपा के यही आलम में कई क्षेत्र क्रमांक में संगठन पदाधिकारी मैदान में है हालांकि भाजपा की और सभी जनपद सदस्यों को अधिकृत नही किया है, लेकिन अजजा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजमेर भूरिया की पत्नी अन्नू भूरिया, पेटलावद अजजा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सोहन डामर की पत्नी अनिता डामर भाजपा से अधिकृत हो कर मैदान मे है। इसी तरह भाजपा के पेटलावद विकास खंण्ड के तीनों मण्डल सहित क्षेत्र के जिला पदाधिकारी या खुद मैदान में है या फिर उनकी पत्नी, माता या पिता ही सरपंच, जनपद के लिए चुनाव मैदान में है।

चुनाव को लेकर नही दिखी दोनों दलों की तैयारी, प्रत्यशियों के चयन के लिए नहीं हुई अहम बैठक

भाजपा जिला अध्यक्ष अपने कार्यकाल के शुरुवात में ही ऐसे घिरे की संगठन की और से चुनाव की तैयारी को लेकर मंडल स्तर पर कोई बैठक नही की गई, जिसमें सरपंच ,जनपद ओर जिला पंचायत के लिए एक प्रत्याशी पर राय बनाई जा सके। जिसके चलते मनमाने ढंग से कार्यकर्ताओ ने नामांकन दाखिल कर दिए, कुछ क्षेत्र में तो मुकाबला भाजपा वर्सेस भाजपा ही हो गया है। तो कई स्थानों पर भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता नामांकन तक दाखिल नही कर सका, जिसका मुख्य कारण क्षेत्र में संगठन के पदाधिकारियों का खुद के चुनाव मैदान में उतरना है। वही जिला संगठन की और से इस ओर कोई ध्यान नही दिया गया अब भाजपा मैदान में उतरे प्रत्याशीयो में से ही किसी पर अपनी छाप लगाने की तैयारी में है। जहॉ भाजपा के एक से ज्यादा कार्यकर्ता मैदान में है वहा भाजपा जो जीता वो अपना की पॉलिसी पर काम कर रही है। इस मामले में कांग्रेस की स्थिति और भी दयनीय है जिनके पास चुनाव मैनेजमेंट का कोई प्रारूप ही नही है, ज्यादातर जगहो पर खास कर जनपद की सीटों पर कोई प्रत्याशी अधिकृत कर के नही उतारा और जो मैदान में उतरे है उसमें छाटो-बिनो की स्थिति है। बरवेट क्षेत्र की सामान्य सीट पर मैदान में उतरे चारो प्रत्याशी भाजपा से जुड़े हुए है, यहाँ कांग्रेस अपना प्रत्याशी तक नही उतार सकी है। जबकि क्षेत्र में विधायक खुद नामांकन दाखिल होने से पहले घंटो समय बिता कर आये अब अपनी साख बचाने के चक्कर मे मैदान में उतरे चार भाजपाई में से एक को समर्थन देने की बात कर रहे हैं।

रोचक होने है मुकाबले, भाजपा के संगठन की साख दाव पर

न्यायलय के पचड़ों में उलझी प्रथम चरण की प्रक्रिया के कारण चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशीयो में भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई, ऐसे में यहां होने वाले चुनाव काफी रोचक होने की संभावना हैं। अन्य विकास खंडों के मुकाबले पेटलावद विकास खण्ड को तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला है और आधी अधूरी तैयारियों के बीच भाजपा के संगठन की साख दाव पर लग गई हैं, तथा यहां के आने वाले परिणाम से जिले में होने वाले चुनावो के परिणाम को भी प्रभावित करेगे ये तय है।

सरपंच पद के 524 व पंच पद के 1911 व 19 जनपद सदस्य पद के लिए फार्म हुए जमा, आज फार्म खीचने की आखरी तारिख

माही की गूंज, थांदला।

लंबी जद्दोजहद के बाद त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम व द्वितीय चरण के नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने के अंतिम दिन केंद्रों पर भारी गहमागहमी रही। पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार न्यायालय प्रक्रिया की वजह से और असमंजस में थे, साथ ही दावेदारों ने नामांकन भरने की होड लग गई। लगभग सभी केंद्रों पर भारी भीड़ जमा रही, सरपंच पदों व पंच पदों के नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने के लिए विकासखंड स्तर पर 11 केंद्र बनाए गए थे। वही जनपद के लिए फार्म अनुविभागीय कार्यालय में दिए गए नामनिर्देशन का अंतिम दिन होने से नामांकन जमा करने पर जमानत राशि जमा करने के लिए लाइन लगाना पड़ी और टोकन वितरित कर देर रात तक प्रक्रिया चलती रही। फार्म की जांच में स्थिति स्पष्ट होगी क्योंकि फार्म की संख्या बहुत ज्यादा होने से जांच में समय लग रहा है।

जनपद सदस्यों के नामांकन फार्म की जांच में भाजपा नेता पूर्व जनपद अध्यक्ष दिलीप कटारा का एक फार्म निरशत किया गया रिटर्निंग अधिकारी दपस बोडा ने बताया कि, कटारा द्वारा जनपद पंचायत से नामांकन दाखिल किया था लेकिन उन्होंने पहले वार्ड क्रमांक 2 का नामांकन प्रस्तुत किया था इस वजह से बाद में वार्ड क्रमांक 6 का नामांकन निरस्त किया गया इस प्रकार 143 नाम निर्देशन पत्रों में से 142 नामांकन विधि मान्य पाए गए।

पंचायत चुनाव की हुकार के बाद भी पलायन जारी

माही की गूंज,झाबुआ।

ग्रामीणजन जरूरी सामान भरकर पलायन पर।

माता-पिता के साथ बच्चे भी पलायन पर।

आदिवासी बाहुल जिले में विकास व मजदुरों को पर्याप्त रोजगार देने का सरकार का दावा पंचायत चुनाव की हुकार के बाद भी मजदुरों का हो रहा पलायन सरकार के दावे को खोखला साबित कर रही हैं। जिले मे पलायन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, प्रतिवर्ष जिलेभर से हजारों की संख्या में ग्रामीण महिला-पुरूष अपने परिवार के साथ काम के लिए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि के बड़े शहरों की ओर कुच कर जाते है। पलायन रोकने के लिए पिछ्ले लंबे समय से शासन-प्रशासन द्वारा किए जा रहे दावे जमीनी स्थल पर महज खोखले ही साबित हुए है।

नतिजन ग्रामीण अंचलों से पलायन का क्रम अब भी जारी है। विगत एक माह से वर्षाकाल में खरीफ सीजन के बाद अब शीतकाल में रवि सीजन में ग्रामीणजन काम की तलाश में गुजरात और राजस्थान के बड़े शहरों की ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहे है। जिले के रेल्वे स्टेशनों, बस स्टेडों पर इनकी भीड़ देखी जा सकती है। ग्रामीण स्वयं तो पलायन कर रहे है, साथ मे अपने बच्चों को भी ले जा रहे है। जिससे उनका भविष्य भी अंधकारमय होगा, वह शिक्षा से वंचित रहने के साथ शोषण का भी शिकार होंगे।

गुजरात एवं राजस्थान में काम करने पर मिलता है अच्छा पैसा

झाबुआ के बस स्टेंड से गुजरात के राजकोट जा रहे ग्रामीण दंपति वसना एवं रमिला सिंगाड़ से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि, गुजरात और राजस्थान में काम करने पर उन्हें अच्छा पैसा मिलता है और रहने तथा भोजन की व्यवस्था भी कंपनी के ठेकेदार की ओर से की जाती है। वहीं जिले में वर्तमान में योजनाएं ठप्प पड़ी होने से ना तो काम मिल रहा है और ना ही समय पर मजूदरी मिलती है, ऐसे में रोजगार के लिए गुजरात और राजस्थान जाना हमारी मजबूरी है।

होते है गंभीर बिमारियों का शिकार

पलायन पर जाने वाले अधिकांशतः ग्रामीणजन गुजरात और राजस्थान में केमिकल और सीमेंट फेक्ट्रियों में कार्य करने से कई तरह-तरह की बिमारियों का शिकार हो जाते है। जिसमें मुख्य रूप से पत्थर, गिटटी आदि तोड़ने से सांस संबंधी बिमारियों, टीबी और कुपोषण के साथ जहरीली फेक्ट्रीयों में कार्य करने से कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस तरह के ऑकड़ों में जिले में तेजी से वृद्धि हुई है। इन पर अंकुश लगाने के शासन-प्रशासन को चाहिए कि, वह बारह मासी ग्रामीणों को उनके गांव में ही पर्याप्त काम देने के साथ समय पर मजदूरी भी दी जाए। साथ ही इस कार्य में बिचौलियों, दलालों और भ्रष्टाचारियों की भूमिका को भी पूरी तरह समाप्त किया जाए।

पंचायत चुनाव पर पड़ेगा असर

वर्तमान में ग्रामीणों का तेजी से पलायन होने वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होने से निश्चित ही इसका असर मतदान पर पड़ना है। एक तरफ ग्रामीणों को कोरोना की तीसरी लहर का भय सता रहा है, तो ऐसे मे 2 जून की रोटी की तलाश मे पलायन करने को विवश है। इस बार पंचायत चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम रहने के साथ सीधा असर बाजारों में रोनक और व्यापारियों के व्यवसाय पर भी पड़ेगा।

जैन समाज द्वारा समझौता, मन्दिर निर्माण नही करने से

सनातन धर्मावलम्बियों ने सर्वानुमति से मन्दिर निर्माण करने का लिया निर्णय

माही की गूंज, थांदला।

14 वर्षो से नगर की एतिहासिक धरोहर नृसिंह-ऋषभदेव मन्दिर के चले आ रहे विवाद के निराकरण के लिये नृसिंह भक्त मण्डल की पहल पर सनातन धर्मावलम्बियों की गणेश मन्दिर में आयोजित बैठक में सर्वसमाजजनों ने एक मत से मुर्ति पूजक जैन समाज द्वारा नौ वर्षो से ध्वस्त किये गये भक्त संत मलूकदास के प्राचीन पुरातात्विक मन्दिर का पूर्ननिर्माण करने में असफल रहने से वृहत जन सहयोग से मन्दिर निर्माण करने का संकल्प लिया।

स्मरण रहे भक्त मलूकदास जी ने प्राचीनकाल में नगर के मध्य दिपमालिका के साथ श्रीमद् भागवत के दो अवतार भगवान नृसिंह एवं भगवान ऋषभदेव जी के दो मन्दिरों का निर्माण समभाग सम शिखर सम आसन में करवाया था। चूंकि तत्समय मूर्ति पूजक जैन समाज के पास उपासना स्थल नही होने से एवं मूर्ति पूजक जैन समुदाय भगवान ऋषभदेव को अपना तीर्थंकर मानते थे जिन्हे इन दोनो सयुक्त देवालयों की पूजा अर्चना का भार सोपा गया था।

वर्ष 2007 में इस सयुक्त सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एकात्मता, सामाजिक समरसता के स्मारक जो की सनातन निर्माण शैली में विघमान था जिसके अग्रभाग में दोनो और गणेश प्रतिमॉए मध्य में भैरव जी की प्रतिमॉ स्थापित थी। इसे जैन मन्दिर में परिवर्तित करने की दूर्भावना से देव प्रतिमाओं को हटाने से सनातन धर्मावलम्बियों ने रोष व्यक्त करते हूए एसडीएम को ज्ञापन प्रस्तुत किया, निर्माण कार्य एवं तोड-फोड पर रोक लगाते हूए प्रकरण दर्ज किया गया था । कूछ अर्से बाद पुनः मूर्तिपूजक जैन समाज ने समग्र जैन समाज के साथ मिलकर इन मन्दिरों के जीर्णोद्धार के लिये स्थानिय प्रशासन के मुखिया एसडीएम थांदला की अध्यक्षता में सर्वसमाज की बैठक 10 अक्टुम्बर 2012 को आयोजित करवाई जिसमें मन्दिर जीर्णोद्धार हेतू सर्वानुमति से तय पाया गया कि, मुर्ति पूजक जैन समाज इसके मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करेगा, समान आसन व शीखर रखा जावेंगा । मन्दिर का मुख्य मार्ग उत्तर दिशा की और जहॉ यातायात का व्यवधान नही हो रखा जावेंगा तथा निर्माण के पूर्व नक्शा एवं मॉडल सार्वजनिक किये जाने उपरांत सर्व सम्मत्ति से ही मन्दिर का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायें।

मुर्ति पूजक जैन समाज द्वारा तय उपर्युक्त मापदण्डों का पालन न करते हूए मन माने तौर से जीर्णोद्धार के नाम पर जेसीबी मशीनों की सहायता से मन्दिर का ताबडतोड विधवंस कर दिया गया तथा कूछ समय उपरांत निर्माण कार्य का भूमि पूजन किये जाने से सनातन धर्मावलम्बियों की आपत्ति पर जॉच उपरांत सारे तथ्य सही पाये जाने से निर्माण कार्य वर्ष 2013 से एसडीएम न्यायालय थांदला द्वारा स्थगन आदेश के द्वारा रोका गया है ।

लम्बे समय उपरांत से आज पर्यन्त मूर्ति पूजक जैन समाज की और से सर्वसमाज के निर्णया अनुसार मन्दिर निर्माण की कोई पहल न करते हूए किसी प्रकार का नक्शा मॉडल सक्षम अधिकारी एवं सनातन धर्मावलम्बियों के समक्ष नही किये जाने से मजबूर होकर सनातन धर्मावलम्बियों ने बैठक आयोजित कर नगर की सामाजिक समरसता को बनाये रखने के लिये मन्दिर निर्माण करने का संकल्प लिया है । बैठक में नगर सहित ग्राम परवलिया , सुतरेटी, तलावली, खवासा ,नौगॉवा के सर्वसमाजजन सम्मिलित हूए । जिसमे एक समिति गठित की गई जिसमें सर्वानुमति से सामाजिक कार्यकर्ता अशोक अरोरा को अध्यक्ष , सचिव गगनेश उपाध्याय, कोषाध्यक्ष विनित शर्मा, उपाध्यक्ष क्रमशः मोहन गवली, लक्ष्मण राठौड, राजीव सोनी ,जीवनलाल पाटीदार, जितेन्द्र राठौड, सह सचिव क्रमशः दिनेश नागर, सचिन सौलंकी, रोहित बैरागी ,दिलीप डामौर, बनाये गये। समिति में मुख्य परामर्शदाता नारायण भटट, गिरिश धानक, जगमोहनसिंह राठौर एवं दिलीपराज चौहान के साथ सवंरक्षक डॉ उमेश शर्मा, अशोक चैहान, भेरूलाल वैघ को मनोनित करते हूए सर्वसमाजजन की 21 सदस्यों को कार्यकारीणी में सम्मिलित किया गया ।

इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक अरोरा व सचिव गगनेश उपाध्याय ने बताया कि, सनातन धर्मावलम्बियों की भावना अनुसार मन्दिर नवनिर्माण के लिये शीघ्र ही निर्माण समिति का पृथक से गठन कर आगामी निर्माण कार्य हेतू सभी से तन-मन-धन से सहयोंग करने की अपील की ।

अन्नकूट महोत्सव संपन्न

माही की गूंज, थांदला।

खेड़ापति मंशा पूर्ण हनुमान मंदिर चैनपुरी पर वार्षिक उत्सव एवं स्थापना दिवस पूर्णिमा के अवसर पर अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ। चेनपुरी शिमला के सरपंच मुन्ना मईडा पुजारी मंहत रामदास जी महाराज ने बताया कि, दो वर्षो से कोराना काल में पुजा, अर्चना, हवन कर यह कार्यक्रम किया गया था। लेकिन इस वर्ष पुर्णिमा के अवसर पर हनुमान जी की, पूजा-अर्चना व हवन के पश्चात धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पिपलखुटा के महंत दयाराम जी महाराज ने साधु संतों व श्रद्धालुओ को धर्म जागरण के बारे में बताया, उन्होने भगवान श्रीराम व हनुमान जी के प्रसंग सुनाते भूले राम भजन भी करवाये। तत पश्चात महाआरती की गई आरती के बाद सभी भक्तों, साधु संतों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की कार्यक्रम में पुजन हवन पंडित मनोज उपाध्याय ने सम्पन्न करवाई।

बामनिया पंचायत में त्रिकोणी मुकाबला, पुरुष सीट पर महिला रामकन्या मखाड़ो मैदान में

पूर्व सरपंच, अनुभव, युवा जोश और बागी के बीच कड़ा मुकाबला

माही की गूंज, बामनिया/पेटलावद।

विकास खण्ड की कुल 77 पंचायत में से तीन ग्राम पंचायत बामनिया, रामपुरिया और मुल्थनिया के चुनाव परिसीमन के कारण सभी पंचायतो से अलग दो साल बाद होते थे, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण पंचायत चुनावो में हुई दो साल की देरी ने इन तीन पंचायतो के चुनाव को भी साथ मे ले लिया है। अलग से चुनाव होने के कारण यहां राजनीति का अलग ही मजमा लगता था और पूरे जिले के भाजपा कांग्रेस के छोटे

-बड़े नेता यहां के चुनाव में रुचि दिखाते थे, लेकिन इस बार ज्यादातर नेता अपने खुद के चुनाव में व्यस्त होने के कारण यहाँ बहुत कम संख्या में पहुँचेगे। जिला पंचायत और जनपद सदस्यों के चुनावों के प्रचार में जिले के बड़े नेता जरूर प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आयगे लेकिन सरपंच के लिए बोलना उनके अधिकृत प्रत्याशी के लिए भारी पड़ेगा इसलिए सरपंच पद से नेताओ की दूरी रहेगी ये तय है।

विकास खण्ड की बड़ी पंचायत में से एक बामनिया पंचायत में होगा त्रिकोणी मुकाबला

बामनिया पंचायत विकास खण्ड की बड़ी पंचायत में से एक मानी जाती है। जहॉ सामान्य वोटरों की संख्या अच्छि-खासी है और नजीते भी यही वोटर तय करते हैं, पिछ्ली बार हुए चुनाव में वर्तमान सरपंच रामकन्या मखोड पुरुष के लिए आरक्षित सीट पर सभी प्रतिद्वंद्वीयो को धूल चटा कर 1500 से अधिक मतों से एतहासिक जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी, लेकिन 5 साल के कार्यकाल देखने के बाद रामकन्या मखोड ये राह मुश्किल हो चली है, पुरुष सीट पर पुरुष के नारे के साथ इस बार जो प्रतिद्वंद्वी मैदान में उतरे है, उससे यह के चुनाव रोचक हो चले हैं। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले बामनिया पंचायत में भाजपा के लिए जमीन बचना मुश्किल हो गया है। जिसका मुख्य कारण भाजपा से जुड़े नेताओ का बागी हो कर चुनाव मैदान उतरने के साथ-साथ 5 साल के कार्यालय में पैदा हुए विरोध के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही इस बार मैदान में उतरे दूसरे प्रत्याशी भी पिछ्ली बार की तरह कमजोर नही है जिससे यहां त्रिकोणी मुकाबला होने की पूरी संभावना हैं।

7 प्रत्याशी मैदान में, एक मात्र महिला प्रत्याशी, कौंन होगा बामनिया सिरमौर...?

पंचायत के लिए फ्लिहाल 07 प्रत्याशी में नामांकन दाखिल किया है और किसके ब्यहि नामांकन वापसी की उम्मीद कम ही है, वेसे तो सरपंच पद पिछ्ली बार की तरह अजज़ा वर्ग के लिए अनारक्षित है, जमा हुए 07 नामांकन में से 06 पुरुष तो 01 महिला ने सरपंच पद की दावेदारी की है और बाकी दावेदारों का मुकाबला भी इसी महिला दावेदार रामकन्या मखोड से है, वो वर्तमान में ग्राम पंचायत की सरपंच है।

रामकन्या मखोड

खुशवंत डामर

नंदलाल गामड़

मोती खड़िया

जाने प्रत्याक्षियों के मजबूत और कमजोर पक्ष

रामकन्या मखोड वर्तमान में भाजपा की जिला मंत्री हो कर भाजपा का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन भी प्राप्त है।

कमजोर पक्ष -

पिछले 05 वर्षों में रामकन्या मखोड पर भ्रस्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, चौराहे से अतिक्रमण हटाने के नाम पर हाट बाजार को अन्य स्थान पर शिफ्ट करना और दुकानों को नए स्थान पर ले जाने के असफ्ल प्रयास में भारी किरकिरी उठानी और वर्तमान में स्थिति जस की तस हो कर आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओ की पूछ परख नही कर स्वयं भू नेता बन कर काम करने की पॉलिसी के कारण इस बार रामकन्या मखोड के पीछे कार्यकर्ता की फ़ौज नजर नही आ रही हैं और उसकी के चलते भाजपा के बागी उम्मीदवार उनके सामने मैदान में उतर गए हैं ,कुल मिला कर जनता को जितनी उम्मीद थी उसके मुकाबले रामकन्या मखोड खरी नही उतरी। वही नगर को मिली ढाई करोड़ की नल जल योजना भी जमीन पर सही तरीके के नही उतारी जा सकी।

मजबूत पक्ष -

जनता की मुख्य समस्या पानी की थी , ढाई करोड़ की योजना का लाभ भले ही जनता को नही मिला लेकिन सीमित संसाधनों के बीच पिछले 05 वर्षों में एक बार भी पानी की विकट समस्या नही देखी और यहां नल जल योजना सुचारू रूप से चलती रही ,वॉट्सएप ग्रुप के द्वारा नल सप्लाई की पूरी जानकारी का आदान प्रदान होता रहा जिसका लाभ मिल सकता हैं , रामकन्या के कार्यालय में कचरा वाहन का संचालन शुरू हुआ जिससे नगर में गंदगी और सफाई लगातार चलती रही , कई मोहल्लों में नाली का निर्माण भी किया गया। भाजपा के समर्थन के कारण रामकन्या मखोड के साथ खासा वोट बैंक है जिसे तोड़ने की बड़ी चुनोती विपक्षियों के सामने होगी।

कांग्रेस से अधिकृत युवा खुशवंत डामर देगे कड़ी चुनोती

कांग्रेस बामनिया पंचायत में पिछले दो चुनाव में अपना प्रत्याशी नही जीता सकी यहां तक कि हार का अंतर भी इतना ज्यादा रहा कि दो दुने वोट भी कांग्रेस प्रत्याशी को जीत नही दिला पाते , ऐसे में इस बार कांग्रेस ने युवा और नए चेहरे खुशवंत डामर पर दांव खेला है जो कही न कही भाजपा के वोट बैंक में भी सेंध लगा रहा है साथ ही भाजपा प्रत्याशी के विरूद्ध होने वाली एन्टी वोटिंग के भरोसे कांग्रेस अपने प्रत्यासी पर दांव खेल सकती हैं।

कमजोर पक्ष -

राजनीतिक अनुभव की कमी खुशवंत डामर के सामने चुनौती बन कर सामने होगा।

मजबूत पक्ष -

पढ़े लिखे युवा होने के साथ साथ नगर में सभी वर्गो के साथ सामंजस्य बना कर रखा हुवा है , कांग्रेस का समर्थन मिलने से कांग्रेस का वोट बैंक भी इनके साथ होना तय है वही युवाओं में खासी पकड़ है और भाजपा के कई सहयोगी इस चुनाव में खुशवंत के साथ है , कर्णीसेना के कई कार्यकर्ता खुशवंत के साथ है , कांग्रेस से कोई दूसरा चेहरा भी बागी हो कर मैदान में नही है जिसका लाभ खुशवंत को मिल सकता है। वर्तमान सरपंच के खिलाफहोने वाली वोटिंग भी खुशवंत के साथ जा सकती हैं।

नंदलाल गामड़ कर रहे भाजपा कांग्रेस को बड़ा नुकसान

दो बार के ग्राम पंचायत में सरपंच रह चुके गामड़ परिवार के नंदलाल गामड़ एक बार खुद और एक बार उनकी पत्नी ग्राम पंचायत में सरपंच रह चुके हैं , उनकी खासियत ये है कि उनको जनता ने लगातार मौका तो नही दिया लेकिन जिनको उनके बाद मौका मिला उनका कार्यकाल देख कर जनता ने उन्हें ही वापस चुना, उनके अपने व्यवहार से उनका खुद का वोट बैंक है जो भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया है , नंदलाल गामड़ दोनों दलों के मतदाताओं को अपनी और कर रहे हैं।

कमजोर पक्ष-

दो बार के सरपंच रह चुके नंदलाल गामड़ के साथ कोई बड़ी टीम पीछे नही है वो पूरी तरह से खुद के दम पर मैदान में है उनके पीछे जरूर साइलेंट वोटर है लेकिन खुल कर सामने नही आ रहे। बार-बार पार्टी बदलने की इनकी पॉलिसी इनको बड़ा नुकसान कर रही हैं।

मजबूत पक्ष -

इस बार दो सरपंच रहे नंदलाल गामड़ को ग्राम पंचायत संचालन का खासा अनुभव है , गामड़ की छवि अनुसार इन पर किसी नेता या पार्टी का उतना नियंत्रण नही होता जितना है अन्य रहा है या होता है इनके कार्यकाल में छोटे मोटे कार्य के लिए परेशान नही होना पड़ा। दोनों दलों से टिकिट की मांग कर सकते थे लेकिन स्वतंत्र होकर लड़ना पसंद किया। राजनीतिक प्रभाव की लड़ाई अगर नही होती तो नंदलाल गामड़ दोनों दलों के प्रत्याशीयो के समीकरण बिगाड़ सकते हैं।

भाजपा के बागी मोती खड़िया का प्रदर्शन तय करेगा भाजपा का भविष्य

विगत साथ सालों से मोती खड़िया की पत्नी जनपद सदस्य रही है और एक वोट से जनपद अध्यक्ष का चुनाव भाजपा से अधिकृत हो कर भी हार गये। भाजपा में आपसी सामंजस्य स्थापित नही होने के कारण मोती खड़िया खुद मैदान में उतर कर इस बार बामनिया का सरपंच बन कर गाँव का विकास करने का दावा कर रहे हैं। नगर के काजलीया फलिये में खासा वर्चस्व रखते हैं और वही के वोट के दम पर मैदान में उतरे है , यदि ग्रामीण इलाकों की वोटिंग मोती के पक्ष में एक तरफ हुई तो फिर भाजपा प्रत्यासी रामकन्या मखोड के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती हैं क्योंकि मोती को मिलने वाला वोट सीधा सीधा रामकन्या मखोड का नुकसान है , पार्टी की और से लगातार मोती खड़िया को बिठाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने की ताल ठोक दी है।

इसी प्रकार चुनाव मैदान में काजलीया फलिये से ही पपु डामर भी मैदान में जो खुद भाजपा से जुड़े हैं लेकिन इस बार उनका कहना है की पुरूष सीट पर भाजपा को पुरूष को ही मौका देना था और रामकन्या का कार्यकाल ऐसा रहा नही की उनको दोबारा मौका दे , पपु डामर की पत्नी पिछले कार्यकाल से ग्राम पंचायत की पंच है और पूर्व सरपंच सुगना गामड़ के निधन के बाद 06 माह तक सरपंच का कार्यभार भी इनके पास रहा है। काजलीया फलिये के वोट के दम पर मैदान में उतरे पपु , मोती खड़िया के बाद दूसरे प्रतयाशी है , पपु भी भाजपा समर्थित को सीधा सीधा नुकसान करते दिख रहे हैं। राजेश पवार वर्षो तक विदेश में रह कर लौटने के बाद विगत तीन चार साल से अपना काम काज बामनिया में ही कर रहे हैं और अब सरपंच के लिए मैदान में है एक अन्य प्रत्याशी अशोक चारेल भी मैदान में लेकिन इन दोनों की चुनाव में उपस्थित कितनी रहेगी ये देखना होगा , राजेश पंवार के कारण जरूर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

77 पंचायत में कुल 530 सरपंच प्रत्याशी मैदान में, जनपद में मात्र एक फार्म हुआ निरस्त

सबसे ज्यादा 17 प्रत्याशी मोहनपुरा पंचायत और सबसे कम 02 प्रत्याशी झकनावदा में

माही की गूंज , पेटलावद।

त्रि-स्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया निपटने के बाद फार्म की जाँच का कार्य बुधवार देर शाम तक फार्म की जांच चलती रही पेटलावद विकास खण्ड के 25 जनपद सीट के लिए 164 आवेंदन प्राप्त हुवे थे जिसमें से केवल एक ही निरस्त हुवा है ,अब कुल 163 लोग मैदान में है , मिली जानकारी के अनुसार 77 पंचायतो में कुल 530 सरपंच प्रत्याशी मैदान है सबसे अधिक 17 सरपंच मोहनपुरा पंचायत में नामांकन दाखिल किया है वही सबसे कम 02 प्रत्यासी झकनावदा पंचायत में मैदान में है यहां से एक किन्नर प्रत्याशी ने भी आवेंदन किय्या था लेकिन जाती के मामले में नामांकन खारिज कर दिया गया है , 77 पंचायतो लगभग 2242 पंचों के आवेंदन स्वीकृत होना बताये जा रहे हैं, कुछ वार्डो में पंचों के निर्विरोध होने की भी जानकारी है और कुछ में आपत्ति का निराकरण होना बाकी है जो कि देर रात तक हो पायेगी। कल नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है जिसके बाद कुछ प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं।

मेले का विरोध कहा तक सही...? गरीब व्यापारियों के पेट पर मारी जा रही लात

धर्मांतरण के नाम पर बाहर से आए व्यापारियों को धमकाना कहा तक है उचित, मेले की परमीशन देने के बावजूद संदेह के घेरे में प्रशासनिक व्यवस्था

माही की गूंज, झाबुआ।

दिसम्बर का मेला यानि झाबुआवासियों के उत्साह और उल्लास का मौका। हर साल दिसम्बर में लगने वाले इस मेले का झाबुआवासियों को बेसब्री से इंतजार रहता है, बच्चों में इसको लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाई देता है। मगर इस वर्ष झाबुआवासियों और खास तौर से बच्चों के इस उत्साह, उल्लास पर पानी फिरता नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ संगठनों की स्वार्थ सिद्धी के चलते झाबुआ का यह मेला लगभग अब नहीं लगने की स्थिति में है। सीधे तौर पर कहें तो ''सांडों की लड़ाई में बागड़ का नुकसान'' हो रहा है।

जिले में इन दिनों हिन्दुवादी संगठन धर्मांतरण का विरोध कर रहे है, इस विरोध का मुख्य हिस्सा विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल है। धर्मांतरण का यह विरोध अब कुछ और ही रूप लेता नजर आ रहा है। धर्मांतरण का विरोध समझ में आता है लेकिन दिसम्बर माह में लगने वाले मेले का विरोध इन संगठनों पर कई प्रश्न खड़े कर रहा है। जबकि दिसम्बर माह में लगने वाले इस मेले का जिले में कोई मायबाप नहीं है। शायद किसी को भी यह पता नहीं कि दिसम्बर माह में आयोजित होने वाले इस मेले का आयोजन किसकी तरफ से किया जाता रहा है। हालांकि हर साल प्रशासन इस मेले को लेकर नगरपालिका को परमीशन देता आ रहा है। नगरपालिका भी मेले में लगने वाली दुकानों से राजस्व लाभ लेती रही है। मगर यह सच है कि, इस मेले को लगते हुए बरसो बरस बीत गए। आज तक इस तरह का कोई विरोध इस मेले को लेकर देखने को नहीं मिला। यह पहला मौका है जब यह मेला किसी विरोध की भेंट चढ़ा है। यानि धर्मांतरण के नाम पर आपस में एक-दुसरे का विरोध दो संगठनों के कारण झाबुआवासियों के उत्साह और उल्लास का यह मेला पूरी तरह से भेंट चढ़ चुका है।

मेले का विरोध या प्रशासन को धमकी

पिछले दिनों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी कर एसडीएम एलएन गर्ग को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में कहा गया था कि, 23 से 25 दिसंबर तक क्रिसमस मेले का आयोजन होता है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष आदिवासी जनजाति समाज को अवैध धर्मांतरण कर ईसाई बनाया जाता है, जो गैर कानूनी है। मेले के आयोजन पर रोक लगाई जाए। अगर फिर भी आयोजन होता है और प्रशासन अनुमति देता है तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी।

मेला नही लगने से बाहर से आए झूला-चकरी व्यापारी होते रहे परेशान। वापस खाली हाथ घर लौटने को मजबूर।

बजरंग दल के इस ज्ञापन के बाद प्रशासन के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ी की जवाब क्या दें। सवाल तो यह है कि, विरोधकर्ताओ को यह पता ही नहीं है कि इस मेला का आयोजनकर्ता कौन है। क्योंकि जिस मेले को क्रिसमस का मेला कहा जा रहा है, उससे चर्च प्रशासन का कोई लेना-देना है ही नहीं, और यह बात चर्च प्रशासन पिछले कई वर्षों से कहता भी आ रहा है। तो फिर बजरंग दल के द्वारा जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन का क्या मतलब...? जबकि इस मेले का क्रिसचन समुदाय या चर्च प्रशासन का कोई लेना-देना ही नहीं है। बजरंग दल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में इस मेले को गैर कानूनी बताया गया, मगर इसका कोई प्रमाण नहीं है। साथ ही यह धमकी भी दी गई कि, अगर प्रशासन इसकी अनुमति देता है तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। इस उग्र आंदोलन के मायने और मिनिंग क्या निकाला जाए। यह कैसी विडंबना है कि प्रशासन को ज्ञापन दो और उसमें यह जानकारी दो कि हम उग्र आंदोलन करेंगे। बावजूद इसके प्रशासन मुक दर्शक बना देखता रहेगा।

हिन्दु संगठनों द्वारा दिए गए ज्ञापन की एक और बात है जो समझ से परे है कि मेले में धर्मांतरण का कार्य होता है। यह कैसी और किस तरह की बात है। यह तो हम सब जानते है कि मेले का मतलब क्या होता है। मेले में हर समुदाय के लोग आते है, उत्साह और उमंग के साथ मौज-मस्ती करते है, मेले में लगी दुकानों से खरीददारी करते है। मगर यह पहली बार सुना है कि, मेले में धर्मांतरण भी होता है। हिन्दु संगठनों की यह बात उन्हे हसी का पात्र बनाती है। सार्वजनिक मेले में किस तरह से धर्मांतरण होता है इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। अगर है तो इन संगठनों को वह सार्वजनिक करना चाहिए।

एसडीएम ने दी परमीशन, सीएमओ कहता हमारा कोई लेना-देना नहीं

अब हुआ कुछ यूं कि, प्रशासन ने मेले की अनुमति दे दी। एसडीएम ने उत्कृष्ट मैदान पर मेला लगाने की अनुमति दी। इधर मेले की तैयारी को लेकर बाहर से करीब दर्जन भर वाहनों में झूले-चकरी लेकर व्यापारी पहुंचे। परमीशन के बावजूद प्रशासन इन्हे झूले-चकरी लगाने नहीं दे रहा है। एसडीएम का कहना है कि, हमारे सामने उत्कृष्ट मैदान की रसीद प्रस्तुत की गई थी, सीएमओ नगरपालिका को चाहिए कि अगर वहां मेला नहीं लगना है तो दूसरा स्थान तय कर उसकी रसीद काटे और वहां की निरस्त करे। एसडीएम का यह भी कहना है कि, नगरपालिका से एनओसी के बाद ही अनुमति जारी की गई। अगर आने वाले समय में कोई खेल आयोजन होना है तो इसकी जानकारी और पत्र प्रस्तुत करें। नई जगह का चयन भी करके जानकारी दें। जिस मैदान की परमीशन मिली थी वहां राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था, प्रतियोगिता खत्म होने के बावजूद दुकानदारों व झूला-चकरी व्यापारियों को यहां दुकानें नहीं

हिन्दुवादी संगठनों के विरोध के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्टें देखने को मिली।

लगाने दी गई। नगरपालिका सीएमओ से जब हमने इस संबंध में चर्चा की तो उनका यह कहना था कि, मेले की परमीशन को लेकर उनका कोई लेना-देना नहीं है। जबकि एसडीएम कह रहे है कि, नगरपालिका से एनओसी के बाद ही अनुमति दी गई।

चले जाओ वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा मारेंगे वो अलग

प्रशासन ने मेले की परमीशन तो दे दी लेकिन मेले में आने वाले व्यापारियों को किसी तरह का संरक्षण मिलता प्रशासन की ओर दिखाई नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि बाहर से आने वाले व्यापारी इधर-उधर भटक रहें है, झूले-चकरी नहीं लगाने देने पर इन व्यापारियों ने शहर के बाहर खाली पड़ी जमीन पर अपने वाहन खड़े कर खुले आसमान के नीचे राते गुजारी, इसी उम्मीद में कि कुछ हल निकले और हम दो जून की रोटी कमा सके। मगर यहां भी इन्हे सुकून से नहीं रहने दिया गया।

गुजरात के बड़ौदा से आए झूला-चकरी व्यापारी बताते है कि, हमने झूले चकरी नहीं लगाए है बावजूद इसके कुछ लोग यहां आकर हमें धमका रहे है। वह कहते है कि यहां से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मेले में अगर झूले-चकरी लगाई तो तुम्हारे यह सभी झूले-चकरी गायब हो जाएंगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और मार खाओगे वो अलग, धमकी के बाद कई व्यापारी झाबुआ छोड़कर जा चुके है। जो थोड़े बहुत बचे है वे भी कुछ रास्ता निकलते ही चले जाएंगे। व्यापारियों का कहना है कि, माहौल ठीक नहीं है, मेला लगा भी तो पता नहीं क्या हो जाए यहां आकर हमें काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है इसकी भरपाई करने में बहुत वक्त लगेगा, पहले ही कोरोना और लॉकडाउन के चलते खाने के लाले पड़े हुए है।

संगठनों की दबंगता और प्रशासन का पंगुपन

अब सवाल यह उठता है कि, जब प्रशासन के मन में इतना ही दुगदुगा था तो मेले के लिए परमीशन ही क्यों दी। और अगर परमीशन दे दी थी तो फिर मेले में पहुंचने वाले व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया करानी थी। कुल मिलाकर प्रशासन की यह भुमिका पूरी तरह से संदेह के घेरे में है या प्रशासन पर भी किसी अदृश्य शक्ति का भारी-भरकम दबाव है। अगर ऐसा है तो प्रशासन का अपना कोई वजूद नहीं है और वह एक दम से पंगू और नपुंसक है। धर्मांतरण की लड़ाई में गरीबों की रोजी रोटी पर लात मारना बहुत ही बड़ा पाप है। मेले का यह विरोध कितना सही है यह तो विरोध करने वाले संगठन ही जाने मगर क्रिसमस डे पर ईसाई सामज के जो आयोजन होना है वह तो होंगे ही!

चर्च नहीं करता मेले का आयोजन

इधर चर्च से पीआरओ फादर रॉकी शाह का कहना है कि, दिसंबर में आयोजित होने वाले मेले में चर्च की कोई भूमिका नहीं है। मेले का आयोजन चर्च की ओर से कभी आयोजित नहीं होता है इसमें चर्च की कोई भूमिका नहीं है। यह आयोजन तो नगरपालिका व नगर प्रशासन करता है, उन्हे इससे राजस्व प्राप्त होता है। इस बार चर्च के आयोजन में कोई तब्दीली नहीं है। वैसे ही आयोजन होगा जैसा हर साल भक्ति भाव से होता आया है। विहिप ने जो ज्ञापन दिए है वह उनका कार्य है हम इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नही करते, वह उनका कार्य कर रहे है हम अपना त्यौहार मना रहे है, त्यौहार को लेकर प्रशासन ने पूर्ण व्यवस्था की जवाबदारी ली है और वह पूर्ण व्यवस्था कर रहे है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों से भी सभी चर्चो के लिए लेटर जारी कर दिए गए है कि चर्चो पर पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए।

इस सारे घटना क्रम के बाद हम तो यही कहेंगे कि कामयाब होने के लिए दूसरों की लाईन मिटाने से बेहतर है कि अपनी लाईन बड़ी की जाए।

संपादकीय

भारतीय कूटनीतिक को अफगानिस्तान में मिली कामयाबी

यह भारतीय कूटनीतिक कामयाबी ही कही जाएगी कि, जिस समय इस्लामाबाद में इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के सदस्य देशों की अफ़ग़ानिस्तान के मुद्दे पर बैठक हो रही थी उसी दिन भारत में आयोजित सम्मेलन में मध्य एशिया के पांच इस्लामिक देश भाग ले रहे थे। दरअसल, दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित तीसरे भारत-मध्य एशिया डायलॉग में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान व कजाखस्तान के विदेश मंत्रियों ने शिरकत की। वे इस्लामाबाद जाने के बजाए दिल्ली सम्मेलन में पहुंचे। इस सम्मेलन में जहां मध्य एशिया के इन देशों के बीच व्यापार संबंधी व क्षेत्रीय जुड़ाव पर बात हुई, वहीं अफ़ग़ानिस्तान के मुद्दे पर गंभीर विमर्श हुआ। उल्लेखनीय है कि, इन पांच देशों में से तीन ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा अफ़ग़ानिस्तान से लगती है। अफ़ग़ानिस्तान के हालात पर इनकी चिंता भारत से मेल खाती है। इस सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान में भारत ने इन पांचों देशों के साथ एक सुर में कहा कि, बदले हालात में अब अफ़ग़ानिस्तान की धरती का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिये नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मानवीय संकट से जूझ रहे अफ़ग़ानिस्तान की भरपूर मदद की जाए। नि:संदेह भारत समेत इन देशों की क्षेत्रीय सुरक्षा को अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के आने से खतरा उत्पन्न हुआ है। इन पड़ोसी देशों के व्यापार पर भी प्रभाव पड़ा है। दरअसल, अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिका व नाटो संगठन की वापसी के बाद तालिबान कब्जा होने से भारत की गंभीर भूमिका नहीं रह गई थी। एक वजह यह कि, तालिबान पाक के गहरे प्रभाव में है और पाक नहीं चाहता कि, अफ़ग़ानिस्तान में भारत की कोई भूमिका हो। लेकिन भारत ने कूटनीतिक प्रयासों से इस दिशा में अपनी भूमिका के लिये जगह बनाने का प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि, दस नवंबर को भी इन मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में दिल्ली सम्मेलन हुआ था। महत्वपूर्ण यह कि इसमें रूस और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद थे।

दरअसल, भारत की सोच रही है कि वह मध्य एशिया के देशों से संबंध बेहतर करके अफ़ग़ानिस्तान में अपने कूटनीतिक हितों का पोषण कर पाएगा। इसमें भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह के जरिये मध्य एशिया के इन देशों से जुड़ाव का लक्ष्य भी शामिल है, जिसमें इन देशों में आपसी व्यापार के लिये मालवाहक गलियारा बनाने पर सहमत होना भी शामिल है। अच्छी बात है कि, भारत की चिंताओं में शामिल इन देशों ने अफ़ग़ानिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर कारगर कार्रवाई पर सहमति जतायी। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रावधानों के अनुरूप अफ़ग़ान धरती को आतंकवाद की उर्वरा भूमि बनाने से रोकने के सभी आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया गया। वहीं भारत समेत इन देशों के विदेश मंत्रियों ने सहमति जताई कि, जहां अफ़ग़ानिस्तान की संप्रभुता व अखंडता की रक्षा होनी चाहिए, वहीं सभी अल्पसंख्यक समूहों की भागीदारी वाली समावेशी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त हो, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। प्रयास हो कि, अफ़ग़ानिस्तान में मानवीय अधिकारों का सम्मान किया जाये। तालिबान सरकार बनने के बाद अफ़ग़ानिस्तान की धरती से नशे के कारोबार फलने-फूलने पर चिंता जताते हुए इस पर रोक के लिये सख्त प्रयास करने की जरूरत बतायी गई। सभी सहमत थे कि, नए अफ़ग़ानिस्तान में यूएन की प्रभावी भूमिका हो। वक्त आ गया है कि मानवीय संकट को दूर करने के लिये तुरंत मदद पहुंचाई जाए। साथ ही जातीय अल्पसंख्यकों, महिलाओं व बच्चों के हितों को संरक्षण मिले। नि:संदेह, पाक को इस बात की परेशानी होगी कि इस्लामाबाद में चालीस साल बाद हुए इस्लामिक देशों के सम्मेलन के समांतर भारत ने मध्य एशियाई देशों के सम्मेलन के जरिये कुछ बढ़त तो हासिल कर ली है। नि:संदेह, जनवरी में होने वाले मध्य एशिया-भारत सम्मेलन के बाद यह मुहिम और विस्तार लेगी। वहीं इस्लामाबाद में हुई ओआईसी की बैठक में पारित 31 मुद्दों वाले संकल्पपत्र में भी अफ़ग़ानिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने व मानवीय सहायता पहुंचाने पर बल दिया गया।

आरक्षण के जिन्न को बोतल में बंद करने की तैयारी

आरक्षण को लेकर लगभग सभी राजनैतिक दलों में आरक्षित वर्ग के आधार पर अपना जनाधार बढ़ाने के प्रयास बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। मराठा, जाट, निषाद, पाटीदार, गुज्जर, जाट समुदायों के विशाल आरक्षण आंदोलनों के अलावा पिछड़े वर्ग में सैंकड़ों पिछड़ी जातियां शामिल होने के कारण जातीय आधार पर जनगणना एवं आरक्षण की मांग को लेकर हिन्दी भाषी राज्यों में आरक्षण की राजनीति चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस लड़ाई में न्यायालयों को भी शामिल कर लिया है। जिसके कारण न्यायपालिका और विधायिका के बीच आरक्षण के मुद्दे पर टकराव बढ़ता जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण को स्वीकार नहीं किया है। जिन राज्य सरकारों ने 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण दिया, उसे विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय संगत नहीं माना। इसके बाद भी सत्ता तक पहुंचने के लिए राजनैतिक दल आरक्षण की मांग को 50 फीसदी से ज्यादा स्वीकार करते हुए आरक्षण बढ़ाते हैं। जिसे सुप्रीम कोर्ट से अवैध ठहरा दिया जाता है। इसके बाद भी आरक्षण विवाद में राजनैतिक दल अपने फायदे के लिए आग में घी डालने का कोई मौका नहीं छोड़ते रहे है।

पिछले कई महीनों से जातीय आधार पर जनगणना की मांग तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। बिहार विधानसभा ने जातीय आधार पर जनगणना के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। कई राजनैतिक दलों द्वारा जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकारों से जातीय जनगणना की जानकारी मांगे जाने के बाद, आरक्षण का जिन्न एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों में असर डाल रहा है। मण्डल और कमण्डल की 30 वर्ष पुरानी लड़ाई एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है।

पिछले दो दशक में सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार घट रही है। निजीकरण के बाद अब नौकरियों में आरक्षण का फायदा भी बहुत कम हो गया है। सत्ता पर भागीदारी बढ़ाने के लिए जातीय स्तर पर आरक्षण की मांग बढ़ने से यह मुद्दा चुनावों के दौरान मतदाताओं के समूह पर बड़ा असर डालता है। अतः आरक्षण की वैतरणी में सभी राजनैतिक दल डुबकी लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं।

हाल ही में मध्यप्रदेश के पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की मराठा आरक्षण को लेकर जो याचिका लगी थी, उसमें मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए आरक्षण के मुद्दे पर दोनों राज्यों के लिए समान आदेश पारित करने से मध्यप्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच की लड़ाई सड़कों पर आ गई है। कांग्रेस की ओर से दायर याचिका में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर कोई मांग नहीं की गई थी। परिसीमन और आरक्षण के रोटेशन में शासन द्वारा नियमों का पालन नहीं किये जाने को लेकर याचिकायें दायर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण की सीटों पर रोक लगाने के आदेश से भाजपा को कांग्रेस के उपर ठीकरा फोड़कर पिछड़े वर्ग की सहानुभूति जगाने का एक अवसर मिला। भाजपा नेताओं ने इसे भुनाने के लिए कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा।

वहीं सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर गलतबयानी करने पर भाजपा नेताओं के खिलाफ10 करोड़ का मानहानि नोटिस देकर मैदान एवं न्यायालय के अंदर दो-दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। आरक्षण के मुदृदे पर जिस तरह से जातीय जनगणना की मांग विभिन्न राज्यों में बढ़ रही है। उससे ऐसा लगता है कि आरक्षण के जिन्न को भाजपा ने बोतल में बंद करने की तैयारियां शुरु कर दी है। जातीय आधार पर जनगणना के आंकड़े आने पर अब एससी, एसटी एवं पिछड़े वर्ग की जातियों में जनगणना के आधार पर आरक्षण देने की मांग होगी। जो राजनैतिक एवं संवैधानिक दृष्टि से संभव नहीं होगा। जातीय आधार पर अब देश की आबादी को कई भागों में बांटने की जो तैयारी हो रही है वह संबैधानिक दृष्टि से संभव नहीं है। आरक्षण खत्म करने को लेकर न्यायपालिका का सहारा लेने और आरक्षण के जिन्न को बोतल में बंद करने की केंद्र सरकार की एक कोशिश के रुप में भी इसे देखा जा रहा है।

सनत कुमार जैन

पूर्वांचल पर नजर

पूर्वांचल को विकास की सौगात देने के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण भाजपा को अगले चुनाव में सत्ता तक पहुंचाने का मार्ग बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी से दूसरी बार लोकसभा पहुंचे नरेंद्र मोदी के लिए पूर्वांचल गुडलक जैसा है। यहां से उन्होंने 2014, 2019 लोकसभा चुनाव और 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज किया था। नतीजों में भाजपा को बंपर सीटें भी मिली थी। ऐसे में भाजपा की सोच है कि पूर्वांचल में पार्टी की पकड़ ढीली ना हो और पूर्वांचल के गुडलक को फिर से यूपी चुनाव में भुनाया जाए। वहीं पूर्वांचल में भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों में गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर, गन्ना किसानों का भुगतान, किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा, सड़कों-फ्लाईओवरों का निर्माण जैसी कई उपलब्धियां शामिल हैं। पूर्वांचल में भाजपा की मजबूत पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की कुल 164 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 115 सीटें मिली थीं। वहीं सपा को 17, बसपा 14, कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें हासिल हुई थीं। हालांकि, एक आंकड़ा यह भी है कि पिछले तीन दशक में पूर्वांचल का मतदाता किसी एक पार्टी के साथ हमेशा नहीं रहा। इसी को देखते हुए भाजपा की तरफसे इन क्षेत्रों में विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी गई है। साथ ही पार्टी 2022 के चुनाव में पूर्वांचल को अपने पक्ष में मजबूत करने में जुट गई है। पूर्वांचल में विकास कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं के अलावा भाजपा जातीय समीकरण पर भी ध्यान दे रही है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल की शुरुआत में होना है लेकिन एक तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी से अभी से यूपी मिशन का आगाज कर दिया है। साथ ही यह संदेश भी दे दिया है कि पूर्वांचल और काशी का विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफकरके यह साफकर दिया कि भाजपा अगला चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से हो कर जाता है लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। जिसने पूर्वांचल में अधिक सीटें हासिल कर ली सत्ता उसे मिल गई। इसलिए भाजपा पूर्वांचल में अपनी पकड़ और बढ़त बनाए रखना चाहती है। 2017 में भाजपा सत्ता में तो आई लेकिन पूर्वांचल की 10 सीटों पर उसकी स्थिति कमजोर बनी रही। जहां अपनी जमीनी हालत दुरस्त करने पर पीएम मोदी और सीएम योगी का मुख्य फोकस रहा है। यूपी के पूर्वांचल को हमेशा बीमारू क्षेत्र के रुप में जाना गया। यहां विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मोदी के काशी के सांसद बनने के बाद से विकास ने यहां रफ्तार पकड़ ली और शहर की सूरत ही बदल गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के हिसाब से सक्रियता बढ़ा दी है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी का पूर्वांचल भाजपा के लिए काफी अहम है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का असर अधिक देखा जा रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी कांड भी भाजपा के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में इसका नुकसान पश्चिमी यूपी और तराई बेल्ट में देखने को मिल सकता है। हालांकि पूर्वांचल जिलों में अब भी भाजपा काफी मजबूत नजर आ रही है। इसलिए भाजपा का पूरा फोकस पूर्वांचल के जिलों पर है। मिशन-2022 के लिए माना जा रहा है कि भाजपा पश्चिमी यूपी में होने वाले नुकसान की भरपाई पूर्वांचल में मजबूत होकर करना चाहती है।

सिद्धार्थ शंकर

शुभ और अशुभ

मनुष्य अपने स्वभाव से हारा है और उसका मज़हब, उसकी विचारधाराएँ, उसकी व्यवस्थाएँ उसके व्यवहार से हारी हैं। व्यवहार, जो उसके स्वभाव और चरित्र का आईना है। यह निराशावाद नहीं है। अस्तित्ववाद भी नहीं है। प्रगतिवाद भी नहीं है। कोई वाद नहीं है। सार्वभौम सत्य है।

यह भी कि, सभी मनुष्य एक-से नहीं होते। न कभी थे, न कभी होंगे। बल्कि कोई भी दो मनुष्य, वे (जुड़वाँ सहित) भाई-भाई या भाई-बहन ही क्यों न हों, पिता-पुत्र, माँ-बेटे ही क्यों न हों, हूबहू एक-से नहीं होंगे।

यह तो स्पष्ट है कि, कोई भी दो मनुष्य सूरत-शक्ल से हूबहू एक-से नहीं होते। इसीलिए फ़ोटो पहचान-पत्र की अहमियत है।

किंतु यह भी अनुभव-जन्य सत्य है कि, कोई भी दो मनुष्य स्वभाव और चरित्र से भी हूबहू एक-से नहीं होते। वे भले ही एक ही मज़हब, एक ही सम्प्रदाय, एक ही जाति, एक ही नस्ल, एक ही राष्ट्रीयता, एक ही आर्थिक वर्ग, एक ही शिक्षा और एक ही परिवेश में पले-बढ़े क्यों न हों। तो सभी मनुष्य एक-से न्याय-प्रिय नहीं होंगे, बाहर-भीतर से एक-से अभिन्न नहीं होंगे। एक-से निराडंबर नहीं होंगे। उनकी कथनी-करनी में एक-सा अभेद नहीं होगा। उनमें संवेदनशीलता का, परदुःखकातरता का, दृढ़ता का, आत्म-सम्मान का, लोभ और डर से विचलित न होने के माद्दे का साम्य नहीं होगा।

लेकिन ऐसा नहीं कि न्यायप्रिय, भीतर-बाहर और कथनी-करनी में एकरूप, दृढ़निश्चयी, आत्म-सम्मानी, संवेदनशील, परदुःखकातर, लोभ और डर से न डिगनेवाले होंगे ही नहीं। हर समय होंगे, हर धर्म, हर सम्प्रदाय, हर जाति, हर राष्ट्र, हर खित्ते में होंगे। जैसे अशुभ कभी नहीं मरता, वैसे शुभ भी कभी नहीं मरता। अनुपात बदलता रहता है किंतु बीज कभी नष्ट नहीं होता। अभी भी दोनों जीवित हैं। अभी भी दोनों के बीज मौजूद हैं। इस देश में भी।

इसकी संभावना सतत बनी हुई है कि न्यायप्रिय, भीतर-बाहर से एकरूप, कथनी-करनी में एक, दृढ़निश्चयी, संवेदनशील, परदुःखकार, लोभ और डर से न डिगनेवालों का पलड़ा भारी हो जाए। काल और स्थान के टुकड़ों में ही सही, ऐसा पहले भी हुआ है। कई बार हुआ है। इतिहास गवाह है। तो आगे क्यों नहीं होगा ?

शुभ के ऊपर आने में संख्या-बल से ज़्यादा आत्म-आश्वस्ति का बल काम करता है। शुभ और अशुभ के मुक़ाबले में अशुभ के पशु-बल से अधिक शुभ का आत्म-आश्वस्ति का बल काम करता है। यह आश्वस्ति शुभ में ही हो सकती है। अशुभ कितना भी बलवान हो वह आत्म-अश्वस्ति से महरूम होता है। यह प्रकृति का खेल है और सनातन है। मनोवैज्ञानिक इसकी व्याख्या खोजते फिरें, किंतु इसे काट नहीं पाएँगे।

एक शुभ के हिम्मत करते ही, अनेक शुभ उससे जुड़ने लगते हैं। शुभ को शुभ खींचता है। दबे हुए शुभ को बाहर लाता है। फ़िल्म, नाटक वगैरह में नायक के जीतने और खलनायक के हारने पर यथार्थ जीवन के नायक और खलनायक दोनों ख़ुश होकर ताली बजाते हैं। इसलिए यह तात्विक रूप से निराशावाद नहीं है। अस्तित्ववाद भी नहीं है। कोई वाद नहीं है।

इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भविष्य में जितनी संभावना सम्पूर्ण विश्व में सर्वहारा क्रांति होने की है (संपूर्ण विश्व में हुए बिना पूँजीवादी घेराबंदी उसे वर्गविहीन समाज के लक्ष्य तक पहुँचने ही नहीं देगी), शुभ का पलड़ा भारी होने की संभावना उससे अधिक नहीं, तो कम भी नहीं है।

हाँ, जिनको समस्त मानव-समुदाय के (हमेशा के लिए) दिव्यांतर का भरोसा है, उनके लिए यह लेख अर्थहीन है।

प्रफुल्लसिंह

शैक्षणिक सुधार खोलेंगे रोजगार के द्वार

केंद्र सरकार का कहना है कि, 2018 में प्रोविडेंट फंड की सदस्यता लेने वाले श्रमिकों में 70 लाख की वृद्धि हुई है लेकिन प्रोविडेंट फंड की सदस्यता में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि दो अलग-अलग बाते हैं। 2018 का समय नोटबंदी और जीएसटी का था। इन नीतियों के कारण छोटे उद्योग कम हुए थे और बड़े उद्योग बढ़े थे। छोटे उद्योग ही ज्यादा रोजगार बनाते थे। इसलिए यदि छोटे उद्योगों में 100 कर्मी बेरोजगार हुए तो हम मान सकते हैं कि बड़े उद्योगों में 50 रोजगार बने होंगे। कुल मिलाकर रोजगार में 50 की गिरावट आयी। लेकिन जिन 50 को रोजगार मिला, वे प्रोविडेंट फंड के सदस्य बने, चूंकि वे बड़े उद्योगों में कार्यरत थे। इसलिए प्रोविडेंट फंड की सदस्यता में 50 सदस्यों की वृद्धि हुई जबकि साथ-साथ कुल रोजगार में 50 श्रमिकों की गिरावट आई। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा किए गये सामयिक श्रम सर्वे में कहा गया कि, 2012 एवं 2018 के बीच अपने देश में शहरी बेरोजगारी में तीन गुना वृद्धि हुई है। और गम्भीर विषय यह है कि यदि मान भी लें कि 2018 में 70 लाख नये रोजगार बने तो भी बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं होता क्योंकि अपने देश में हर वर्ष 120 लाख नये युवा श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से यदि 70 लाख को रोजगार मिल भी गया तो भी 50 लाख युवा बेरोजगार ही रह जाएंगे।

समस्या के गंभीर होने के दूसरे संकेत उपलब्ध हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए उपरोक्त सामयिक श्रम सर्वे के अनुसार 2012 से 2018 के बीच शहरी बेरोजगारी की दर में 3 गुना वृद्धि हुई है। इसी सर्वे के अनुसार 2018 में अपने देश में 15 से 24 वर्ष के लोगों में 28.5 प्रतिशत बेरोजगार थे जो कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अधिकतम था। इसी सर्वे के अनुसार 2012 से 2018 के बीच वेतन में भी गिरावट आई है। जैसे मान लीजिये आपका 2012 में वेतन 100 रुपए प्रति दिन था और 2018 में आपका वेतन 110 रुपए प्रतिदिन हो गया। वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन मान लीजिये इसी अवधि में जो टॉफ़ी 2012 में एक रुपए में मिलती थी, वह 2018 में 1.50 रुपए में मिलने लगी। ऐसा हुआ तो आपके वास्तविक वेतन में कटौती हुई। 2012 में आप एक दिन के वेतन में 100 टॉफी खरीद सकते थे। 2018 में एक दिन के वेतन में आपको केवल 55 टॉफी मिलेंगी, चूंकि वेतन में वृद्धि कम और टॉफ़ी के दाम में वृद्धि ज्यादा हुई है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा किए गये सर्वे में कहा गया कि 2012 से 2018 के बीच वास्तविक वेतन में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। अतः बेरोजगारी की समस्या को झुठलाने से काम नहीं चलेगा। इसके मूल कारणों का निवारण करना होगा।

बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण तकनीकी बदलाव है। जैसे पूर्व में बैंक में खाते क्लर्कों द्वारा रखे जाते थे। अब यह कार्य कम्प्यूटर से होने लगा है। बैंक की कई शाखाओं में केवल दो या तीन कर्मी काम करते हैं। कम्प्यूटर ने श्रमिकों की जरूरत को कम कर दिया है। लेकिन साथ-साथ बैंकों का प्रसार बढ़ा है और शाखाओं की संख्या बढ़ी है। इनमें नये रोजगार उत्पन्न हुए हैं। इतिहास पर गौर करें तो किसी समय यातायात का प्रमुख साधन घोड़ा-गाड़ी हुआ करता था। इसके बाद कार का आविष्कार हुआ, जिसके कारण घोड़ा-गाड़ी चलाने वाले बेरोजगार हो गये। लेकिन कार के चलन का विस्तार हुआ। इनके उत्पादन और मरम्मत में नये रोजगार बने। इनके लिए सड़क और फ्लाईओवर बनाने में भी रोजगार बने। इसलिए घोड़ा-गाड़ी में रोजगार में गिरावट के बावजूद यातायात क्षेत्र में कुल रोजगार बढ़े। वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा हमारे सामने है। तमाम कार्य जैसे हड्डी में फ्रैक्चर को पहचानना अथवा खून की जांच करना अब कम्प्यूटर द्वारा किये जाने लगे हैं। ऐसा होने से रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलाजिस्ट के रोजगार पर संकट आने को है। लेकिन जिस प्रकार घोड़ा-गाड़ी के समाप्त होने के बावजूद कार के चलन से कुल रोजगार में वृद्धि हुई; उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तमाम नये उत्पाद बन सकते हैं। जैसे आपके मनपसन्द प्लॉट का सिनेमा बनाना अथवा वीडियो मिक्स करना इत्यादि। अतः हमें अपने युवाओं को रोजगारों की इन नई संभावनाओं को पकड़ने को प्रशिक्षित करना होगा।

यहां प्रमुख समस्या हमारी शिक्षा व्यवस्था की है। वर्तमान में युवाओं का रुझान सरकारी नौकरियों की तरफ बना हुआ है, बावजूद इसके सरकारी नौकरियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन सामान्य शिक्षा वाले प्राइमरी सरकारी स्कूल के टीचर को आज 50 से 70 हजार रुपये प्रतिमाह मिलता है जबकि एक ट्रेंड नर्स अथवा डाटा एंट्री आपरेटर को बमुश्किल 15 हजार रुपये प्रतिमाह मिलता है। इसलिए युवाओं को नर्स अथवा डाटा एंट्री आपरेटर की क्षमता हासिल करने में रुचि नहीं है। उनका पूरा ध्यान सरकारी नौकरी हासिल करने की तरफ रहता है। वास्तविक 'शिक्षा' ग्रहण करने में उनकी रुचि नहीं है। सरकार को चाहिए कि सरकारी कर्मियों और साधारण नागरिकों जैसे नर्स के वेतन के बीच संतुलन स्थापित करे, जिससे सरकारी नौकरी का मोह कम हो और हमारे युवा व्यावहारिक पढ़ाई पर ध्यान दें। इस दिशा में सरकार को प्राइमरी स्तर पर ही अंग्रेजी भाषा और कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे कि युवा आने वाले समय में कम्प्यूटर आधारित रोजगार, जैसे पुस्तकों का अनुवाद करना अथवा वीडियो मिक्स करना जैसे कार्यों को स्वयं कर सकें और अपनी जीविका अर्जित कर सकें।

हमें इस चिंता में नहीं रहना चाहिए कि अंग्रेजी को अपनाने से हमारी संस्कृति की हानि होगी। हमें ध्यान करना चाहिए कि किसी समय हमारी संस्कृति सिन्धु घाटी की भाषा में समझी जाती थी। इसके बाद वही प्राकृत भाषा में परिवर्तित हुई और फिर देवनागरी में। लेकिन संस्कृति की निरन्तरता कायम रही। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी संस्कृति का अंग्रेजीकरण करें जिससे कि हम अंग्रेजी भाषा में उत्पन्न होने वाले रोजगार भी हासिल करें और साथ-साथ अपनी संस्कृति का वैश्वीकरण भी कर सकें। यदि हम अपने वेद, पुराण तथा करपात्रीजी महाराज जैसे विद्वानों की टीकों को सुलभ अंग्रेजी में उपलब्ध करा दें तो हमारी संस्कृति का भी वैश्वीकरण होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। इतिहास की उपयोगिता भविष्य को संवारने के लिए होती है। इतिहास का उद्देश्य कठघरे में जीवित रहने का नहीं होता है।

भरत झुनझुनवाला

गांधीसागर अभ्यारण में चीतों के भोजन की व्यवस्था जोरों पर

चीतल को बसाने के लिए विकसित हो रहा चारागाह

माही की गूंज, मन्दसौर। साहिल अगवान

जिले के गांधीसागर अभयारण्य को अफ्रीकी देशों से लाए जाने वाले चीतों के लिए श्योपुर के कूनो अभयारण्य के बाद दूसरी प्राथमिकता पर रखा गया है और यहां चीते आने की संभावना के चलते वन विभाग ने उनके भोजन के लिए चीतलों को बसाना शुरू कर दिया है। नरसिंहगढ़ सेंचुरी व भोपाल के वन विहार से लगभग 500 चीतल गांधीसागर अभयारण्य में छोड़ना है। अभी तक यहां 280 चीतल लाकर छोड़े जा चुके हैं। चीतलों ने यहां अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया तो चीतों के आने की राह भी आसान हो जाएगी। लगभग 323 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले गांधीसागर अभयारण्य में घास के बड़े-बड़े मैदानों को देहरादून से आए जीव विज्ञानियों ने चीतल व चीतों दोनों के ही लिए अनुकूल माना था। ऐसे में उनके लिए यहां चारागाह विकसित करने से लेकर हर पल उन पर नजर भी रखी जा रही है। नरसिंहगढ़ सेंचुरी से लेकर भोपाल वन विहार से यहां लाकर चीतल छोड़े जा रहे हैं। इनमें मादा चीतल की संख्या ज्यादा है। तो नर चीतल भी लाए गए हैं।

भोपाल के वन विहार से 11 दिसंबर की रात में भी यहां लाकर 22 चीतल छोड़े गए हैं। इसमें 18 मादा और 4 नर चीतल है। विभाग के अमले ने भोपाल से आए वाहन से यहां पूरे अमले की मौजूदगी में चीतल को छोड़ा गया। अब तक कुल 280 चीतल यहां छोड़े जा चुके हैं। इसमें 225 के लगभग मादा तो बाकी नर चीतल हैं। छोड़े गए चीतल के स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर अन्य प्रक्रिया विभाग ने पूरी की। आगामी दिनों में और चीतल यहां छोड़े जाएंगे।

चीतों का भोजन चीतल, चीतल के लिए बना रहे चारागाह

गांधीसागर अभयारण्य क्षेत्र में नवंबर 2020 में पहली बार यहां लगभग 18 चीतल छोड़ गए थे उसके बाद से अब तक लगातार चीतल छोड़े जा रहे है। गांधीसागर में चीतल के लिए चारागाह प्राकृतिक रुप से बने हुए है। इससे चीतल को यहां की परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहां छोड़े गए सभी चीतल पर विभाग का अमला हर दिन निगाह रख रहा है। चीतल के लिए गांधीसागर में पूरी तरह अनुकूल वातावरण तैयार करने में विभागीय अमला लगा हुआ है।

कुनबा बढ़ाने के लिए मादा चीतल अधिक छोड़ी

गांधीसागर अभयारण्य कई प्रकार के वन्यजीवों के लिए अनुकूल है और इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। चीतल की संख्या भी लगातार बढ़े इसके लिए मादा चीतल ज्यादा छोड़ी जा रही है। अब तक छोड़े गए चीतल में मादा चीतल 221 है जबकि नर चीतल की संख्या कम है।

डीएफओ आदेश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि, अफ्रीकी चीतों को गांधीसागर अभयारण्य में लाने की मंजूरी मिलने के बाद यहां उनके अनुकूल माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। अब तक 280 चीतल छोड़े जा चुके हैं। उनके लिए चारागाह विकसित किए जा रहे हैं। 500 से अधिक चीतल आने के बाद यहां चीते लाए जाएंगे। अभी 22 चीतल वन विहार भोपाल से लाकर छोड़े गए हैं। अब तक छोड़े गए सभी चीतल बेहतर तरीके से यहां जीवनयापन कर रहे हैं।

मंडी में लहसुन उपज के सही दाम नही मिलने से नाराज किसान ने अपनी ही फसल में लगाई आग

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के एक किसान ने अपने लहसुन में आग लगा दी। किसान लहसुन की फसल को लेकर मंडी में बेचने आया था। यहां पर जब उसे मनमुताबिक दाम नहीं मिला तो किसान ने गुस्से में आकर बाइक से पेट्रोल निकाला और लहसुन में आग लगा दी। इस दौरान किसान 'भारत माता की जय' के नारे भी लगा रहे थे। कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है।

ढाई लाख खर्च, मिल रहे थे बस एक लाख

बताया जाता है कि, इस वर्ष मंदसौर में लहसुन की फसल काफी अच्छी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह किसान उज्जैन जिले से लहसुन की फसल लेकर आया था। इसके लिए उसने 5 हजार रुपए खर्च किए थे। लेकिन मंडी में उसके लहसुन का दाम केवल एक हजार सौ रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रहे थे। इसी बात से नाराज होकर उसने अपने लहसुन को आग को हवाले कर दिया। उधर मंडी में आग लगने की खबर सुनते ही मंडी के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। साथ ही मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई। जिस किसान ने अपने लहसुन में आग लगाई है नाम शंकर है। किसान शंकर ने बताया कि, उसने लहसुन की फसल उगाने में ढाई लाख रुपए खर्च किए थे। लेकिन इसके एवज में उसे सिर्फएक लाख रुपए ही मिल रहे थे।

कांग्रेस ने साधा निशाना

उधर कांग्रेस ने इस मामले पर सवाल उठाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, 'कमलनाथ जी ने छिन्दवाड़ा में कहा कि मंदसौर में लहसुन की खेती वाले किसान परेशान हैं। उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहा है और मंदसौर मंडी में एक किसान ने कम दाम मिलने पर भारत माता की जय बोलते हुए अपनी लहसुन की फसल में आग लगा दी।

जावरा नगर जुड़ेगा तलवाड़ा डेम से, 53 करोड़ की पेयजल योजनाएं हुई स्वीकृत

माही की गूंज, रतलाम।

समूह जल प्रदाय योजना के तहत जावरा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जावरा नगर को भी तलवाड़ा बैराज से जोड़ा गया है। विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 53 करोड़ की लागत से 61 योजनाएं स्वीकृत की है।

जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय के प्रश्न पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उक्ताशय की जानकारी दी है। श्री चौहान ने बताया कि, समूह जल प्रदाय योजना के तहत जावरा विधानसभा क्षेत्र को प्रस्तावित तलावड़ा डेम से जोड़ा गया है। जावरा नगर को भी इसमे सम्मिलित किया गया है। बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति हेतु उद्योग विभाग द्वारा पृथक से कार्ययोजना बनाई जाएगी। जावरा विधानसभा क्षेत्र में जावरा व पिपलोदा विकासखण्ड के 61 स्थानों में जल जीवन मिशन के तहत एकल रेट्रोफिटिंग व नवीन जल योजनाएं स्वीकृत की गई है। लगभग 53 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत इन योजनाओं में से अधिकांश योजनाओं के कार्य प्रारंभ हो गए है जिनमे जावरा विकासखण्ड के 28 ग्राम सम्मिलित है जिसमे कामलिया, नयानगर, नेतावली, रीछाचांदा, माँगरोला, रोजाना, मोयाखेड़ा, अरनिया पीथा, इस्लामनगर, ढोढर, असावती, रसूलपुर, इस्माईल पुरा, मुंडलाराम, गोंदीशंकर, गोंदी धर्मसी, लालाखेड़ा, बामनखेड़ी, रिंगनोद, पिपल्याजोधा, बहादुरपुर जागीर, रोला, कुम्हारी, गोठड़ा, बनवाड़ा, नन्दावता, ताराखेड़ी, सरसौदा ग्राम है जबकि पिपलोदा विकासखण्ड। अंतर्गत 33 ग्राम सम्मिलित है जिसमे आजमपुर डोडिया, शककरखेड़ी, कलालिया, भाटखेड़ी, बोरखेड़ा, धामेडी, हतनारा, नोलखा, पिण्डवासा, तालिदाना, नांदलेटा, सुजापुर, सुखेड़ा, रिछादेवड़ा, कमलाखेड़ा, चिपिया, बरगढ़, अरनिया गुजर, रणायरा , पिंगराला, पंचेवा, नवेली, गुडरखेड़ा, मामटखेड़ा, कन्सेर, बिलन्दपुर, कुशलगढ़, बडायला चौरासी, माननखेड़ा, झाँझाखेड़ी, हल्दूनी लसूड़िया नाथी व रामगढ़ है।

सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए डॉ. पांडेय

भारतीय संसदीय संस्थान द्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठक में विधायक डॉ. राजेन्द्र पांडेय सम्मिलित हुए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोविड काल व कोविड काल के बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में किए गए कार्यो व लोगो को जागरूक बनाने के लिए किए प्रयास पर चर्चा हुईं। बैठक में आईपैड व डब्लूएच के संयुक्त प्रयास से किए कार्यो की पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।

जंगल से पेड़ काट बना रहे स्वादिष्ट मिठाइयां

माही की गूंज, भानपुरा।

तहसील क्षेत्र में वन माफिया सक्रिय टानो से लकड़ी काटकर मिष्ठान की दुकान पर जलाई जा रही है। दुकानदार मिठाई नमकीन व अन्य चीजें बनाने के लिए आज भी दुकानों पर लकड़ी का उपयोग कर रहे है। लकड़ी जंगल से लाकर जलाई जा रही है। भानपुरा नगर में स्थित सदर बाजार टाई कि दुकान, नया बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड की कई दुकानों पर आज भी लकड़ी की भट्टी का उपयोग कर मिठाई नमकीन अन्य सभी चीजें बनाई जा रही। कार्रवाई न होने से अधिकारियों व कर्मचारियों की वन माफिआओं से सांठ-गांठ उजागर हो रही है। कभी कभार छोटे लकड़ी चोरों पर कार्रवाई कर स्थानीय वन विभाग के अधिकारी अपनी पीट थपथपा लेते हैं। लेकिन दबंग व प्रभावशाली वन माफिआओं पर कार्यवाही करने में विभाग नाकाम हो रहा हैं।

गणना : भानपुरा वनक्षेत्र में बड़ी तेंदूए की संख्या

माही की गूंज, मंदसौर।

गांधीसागर अभ्यारणय सहित पांच वनक्षेत्रों में की गई गणना के दौरान मिले है। अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा गणना पूरी कर आलाअधिकारियों को रिपोर्ट दी गई है। वे अब तैयार हो रही है। रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा की कौन-कौन से वन्यप्राणियों की संख्या में बढोत्तरी हुई है। गणना में एक बहुत ही बड़ी बात सामने आई है कि, जिले के पांच वनक्षेत्रों में मंदसौर और गरोठ वनक्षेत्र में तेंदूए नहीं है। वहीं गांधीसागर अभ्यारणय और भानपुरा वनक्षेत्र में ही तेंदूए की उपस्थिति गणना के दौरान बेहतर दर्ज हुई है। जिससे अधिकारियों को भारी उम्मीद है कि, तेंदूओं की संख्या पहले से बढ़ी है।

जानकारी के अनुसार जिले में पांच वनक्षेत्र है। इसमें गांधीसागर पूर्व और पश्चिम, भानपुरा वनक्षेत्र, गरोठ वनक्षेत्र और मंदसौर वनक्षेत्र है। जिनमें एक दिसबंर से लेकर सात दिसबंर तक गणना का कार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार पहली बार हाईटेक तरीके से गणना कार्य हुआ है। गणना एमटाइप इकोलॉजिकल मोबाइल एप से किया गया है। इसको लेकर अब गणना रिपोर्ट बनाई जा रही है।

मांसाहारी वन्यप्राणियों की ट्रेल से गणना

जानकारी के अनुसार शाकाहारी और मांसाहारी वन्यप्राणियों की गणना दो अलग-अलग तरीके से होती है। इसमें शाकाहारी वन्यप्राणियों की गणना ट्रांजेक्ट लाइन के अनुसार की जाती है। इसमें बकायदा एक पाथ बनाया जाता है। जिसके अंतर्गत गणना की जाती है। वही मांसाहारी वन्यप्राणियों की गणना ट्रेल के अनुसार की जाती है। इसमें पांच किलोमीटर कम से कम चलना पड़ता है। गणना कार्य में वनविभाग के अधिकारी और कर्मचारियों मिलाकर पूरा किया। गणना। वही वाइल्डलाइफ विशेषज्ञ भी मौजूद थे। गांधीसागर और भानपुरा वनक्षेत्र में तेंदूओं की उपस्थिति बहुत अच्छी दर्ज हुई है। जिससे अधिकारी बहुत खुश है। और बलवित संभावनाएं जता रहे है कि संख्या बढ़ी है। मदंसौर और गरोठ वनक्षेत्र में तेंदूए की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। इनके साथ सियार, लकडबग्घा की भी संख्या बढ़ी है। वही चिंकारा, हिरण सहित अन्य की संख्या बढने् की पूरी उम्मीद है।

डीएफओ मंदसौर आदर्श श्रीवास्तव ने बताया कि, एसेंमेंट का कार्य एक दिसबंर से 7 दिसबंर तक था। जो पूरा हो गया है। इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पांच वनक्षेत्र में यह कार्य किया गया है। गांधीसागर और भानपुरा वनक्षेत्र में तेंदूओं की बेहतर उपस्थिति दर्ज हुई है।

शासकीय महाविद्यालय पोलायकला में मनाया युवा उत्सव

माही की गूंज, शाजापुर।

शाजापुर शासकीय महाविद्यालय पोलायकला में शासन के निर्देशानुसार 19 से 21 दिसंबर तक तीन दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। 19 दिसंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित तथा सरस्वती वंदना के साथ किया गया। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य संजय सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की तथा घोषणा करते हुए बताया कि, यह यह युवा उत्सव छात्र-छात्राओं के बहुमुखी विकास के उद्देश्य हेतु आयोजित किया जाता है। इसके पश्चात वाद विवाद प्रश्न मंच तथा रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। द्वितीय दिवस में एकल नृत्य, मूक अभिनय तथा तृतीय दिवस में एकल गायन समूह गायन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसमें छात्र-छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर युवा उत्सव प्रभारी उमाशंकर कुल्हारे ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा की। विजेता छात्र, छात्राएं 28 और 30 दिसंबर को जिला स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का आभार युवा उत्सव प्रभारी उमाशंकर कुल्हारी ने माना।

विजय दिवस की 50 वीं वर्षगांठ पर किया पूर्व सैनिकों का सम्मान

माही की गूंज, शुजालपुर।

भारत-पाकिस्तान युद्ध 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 50 वी वर्षगांठ पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले सैनिको व पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम 1971 के युद्ध में अपनी शहादत देने वाले शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्व. इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। स्वागत भाषण जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना द्वारा दिया गया। तत्पश्चात पूर्व सैनिकों का सम्मान साल, साफा, फूल-माला व स्मृति चिन्ह देकर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 1971 के युद्ध में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर भाग लेने वाले नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर सीवी मिश्रा थे। सर्वप्रथम जिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा डॉक्टर सीवी मिश्रा का स्वागत किया गया, तत्पश्चात अन्य अतिथि द्वारा व कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी द्वारा सैनिकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को मुख्य रूप से कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी व चिकित्सक डॉक्टर सीवी मिश्रा द्वारा संबोधित किया गया।

कार्यक्रम में डॉक्टर सीवी मिश्रा ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि, भारत-पाकिस्तान के युद्ध के समय में नया-नया मेडिकल ऑफिसर के तौर पर आर्मी में ज्वाइन हुआ था और मेरे ज्वाइन होने के एक वर्ष बाद ही 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मुझको भी अपनी सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ। जिसमें मैंने घायल हुए सैनिकों का इलाज किया व हम लोग एक वर्ष तक भारत के द्वारा जीते गए पूर्वी पाकिस्तान में रहे। डॉक्टर सीवी मिश्रा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की दृढ इच्छा शक्ति को नमन किया।

कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी ने बताया कि, युद्ध बातों से नहीं इरादों से जीते जाते हैं। उन्होंने कहा कि, लोग आजकल इतिहास नहीं बदल पाते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने 1971 में दक्षिण एशिया का भूगोल बदल दिया था और भारत के बंटवारे कि टीस जो उनके मन में थी उसका बदला। इंदिरा ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके नया बांग्लादेश का निर्माण कर लिया। साथ ही कुणाल चौधरी ने कहा कि, हमारे प्रधानमंत्री मोदी मुंह से बड़े-बड़े गोले फेंकते हैं लेकिन आज तक 1 इंच भी जमीन पाकिस्तान से वापस नहीं ले पाए न ही पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय करा पाए। वहीं इंदिरा ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी सेना के द्वारा लाहौर तक तिरंगा लहरा दिया था व पाकिस्तान के लगभग एक लाख सैनिकों को समर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। ढाका पर भारतीय सेना ने कब्जा करके बांग्लादेश जैसे नए देश का निर्माण कर दिया था जबकि चीन का पूरा समर्थन पाकिस्तान को प्राप्त था उसके बाद भी इंदिरा जी ने अपने दृढ़ निश्चय से ऐसा किया इसे कहते हैं असली 56 इंच। उन्होंने कहा कि, देश चलाने और मुंह चलाने में फर्क होता है।

कार्यक्रम को अन्य अतिथियों रामवीर सिंह सिकरवार, गजेंद्र सिंह सिसोदिया, रचना जैन, अशोक परमार, केदार मेवाड़ा द्वारा भी संबोधित किया गया। कार्यक्रम में 2 दर्जन से अधिक पूर्व सैनिक उपस्थित थे साथ ही कई गणमान्य नागरिक कांग्रेसन व आम लोग भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में चिकित्सक डॉक्टर सीवी मिश्रा का जन्मदिन होने पर केक काटकर उनका जन्मदिन भी मंच पर मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मंगल सिंह राठौर ने किया व आभार वरिष्ठ पूर्व पार्षद महेंद्र नाहर ने व्यक्ति किया। उक्त जानकारी विधानसभा कांग्रेस के प्रवक्ता अजय मोरटे ने दी।

पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूर्ण

माही की गूंज, मंदसौर।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अतंर्गत जिला पंचायत सदस्य के लिए 41 व जनपद पंचायत वार्डो के लिए 287 तथा ग्राम पंचायत में सरपंच के लिए एक हजार 365 तथा ग्राम पंचायत में पंच के लिए 3 हजार 997 अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन हेतु नामांकन दाखिल किए गए है। उल्लेखनीय है कि, जिलें में प्रथम चरण में 6 जनवरी 2022 को मंदसौर विकासखण्ड में निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।

वार्डो में अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र लेने की अंतिम तिथि 20 दिसम्बर दोपहर 3 बजे तक नियत थी। नाम वापस लेने का अंतिम दिन 23 दिसंबर है। 23 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी अपना नाम ले सकते है। 23 दिसंबर के दिन ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीक आवंटित कर दिए जाएंगे। मतदान 6 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।

तेजू बाबा उज्जैन कीर समाज धर्मशाला के अध्यक्ष मनोनीत

माही की गूंज, शाजापुर।

कीर समाज धर्मशाला पर सामाजिक कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसमें मध्य प्रदेश के कई जिलों से समाज के कार्यकर्ता व वरिष्ठजन शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण व विकास के लिए नई कार्यकारिणी का गठन करना था। जहां हजारों समाजजनों की उपस्थिति में धर्मशाला की जिम्मेदारी देते हुए तेजू बाबा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कीर समाज ने अपनी एकता और अखंडता का परिचय देते हुए सर्व सहमति से श्री कुबेर गौ सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कीर समाज के सक्रिय व कर्मठ कार्यकर्ता तेजू बाबा को कीर समाज धर्मशाला अध्यक्ष पूर्ण बहुमत से बनाया गया। इस अवसर पर समाज के कई कार्यकर्ताओं व उनके चाहने वालों ने शुभकामनाएं देते हुए पुष्पमालाएं पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर कीर समाज धर्मशाला की पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष श्याम लाल कीर ने एकता का परिचय देते हुए व समाज का और भी प्रभावित विकास हो सके इस हेतु अपना इस्तीफा प्रस्तावित करते हुए बाबा को शुभकामनाएं दी व कीर समाज की धरोहर रूपी धर्मशाला को आगामी और भी महत्वपूर्ण रूप व सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया ।

बाबा ने बताया कि, मैं आपकी मंशा अनुरूप समाज कल्याण हेतु हर संभव प्रयास व कार्य करूंगा। आप सभी समाज जनों द्वारा दी गई जिम्मेदारी पर खरा उतरूंगा व समाज को एक ही मंच पर एक साथ खड़ा करने का प्रयास करूंगा।

भूकंप आने से मची भगदड़ की काल्पनिक घटना मानकर, एनडीआरएफ ने किया मॉकड्रिल

2 घण्टे रेस्क्यू कार्य प्रदर्शन में 3 घटना से पहुंचाई राहत

माही की गूंज, खरगोन।

देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पर देशभर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस के तहत सभी विभागों द्वारा अपने अधीन आने वाली गतिविधियों या कार्यवाही के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। इसी सिलसिले में बुधवार को 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वाराणासी ने महेश्वर के किला घाट पर जॉइंट मेगा मॉक एक्सरसाइज का सफल संचालन किया। खरगोन जिले में ऐसा पहली बार हुआ है जहां उच्च स्तर के दल ने किसी ऐतिहासिक स्थल पर काल्पनिक घटना मानकर बचाव व राहत का प्रदर्शन किया है। एनडीआरएफ के कमांडेंट श्री मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अमृत महोत्सव में ऐतिहासिक इमारतों व राष्ट्र की धरोहरों पर आपदा के राहत कार्य आयोजित किये जा रहे है। इसी के तहत अहिल्या फोर्ट पर सफल प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा, एसडीएम ओमनारायण सिंह, एसडीओपी डीआरएस चौहान, एनडीआरफ के उपनिरीक्षक मनीष चौबे, सत्यजीत सिंह एवं राम बहादुर सिंह, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी फायर ब्रिगेड, प्रभारी होमगार्ड, एसडीईआरएफ सहित जनपद के सभी एनजीओ तथा स्कूल के बाल बालिकाएं, एनसीसी के जूनियर तथा सीनियर डिवीजन कैडेट्स, नेहरू युवा केंद्र के प्रभारी तथा जिले के अपदा बचाव के सदस्य व सभी हितधारक उपस्थित रहे।

शिवरात्रि के अवसर पर 6.8 तीव्रता का आया भूकंप और बचाव व राहत कार्य मे लग गए

महेश्वर में नर्मदा तट स्थित अहिल्या क़िले और घाट पर अक्सर पर्यटकों से भरा रहता है। लेकिन बुधवार को एक अलग ही तरह के लोग यहां मौजूद थे। यहां आपदा और राहत के प्रदर्शन के लिए दल अपना अभ्यास करने वाला था। इसके लिए दल ने महाशिवरात्रि के अवसर पर काल्पनिक रूप से 6.8 रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता भूकम्प आने से भगदड़ मचने की घटना रची। पूर्व तैयारी अनुसार 12 बजे भूकम्प आने मची भगदड़ की जानकारी मिली। एनडीआरएफ दल तुरंत घटना स्थल पर पहुँचा और आपदा में बचाव के कार्य प्रारम्भ किये। काल्पनिक घटना के तीन सीन रचे गए। एक भूकंप आना, दूसरा अमोनिया गैस का रिसाव और तीसरा पानी में डूबने को शामिल किया गया। भगदड़ मचने और अमोनिया के गैस रिसाव तथा भगदड़ के बाद लोग अपने आपको बचाने के लिए नर्मदा में छलांग लगाने लगे। बस इन गतिविधियों में बचाव करना था। इसके लिए तीन दलो ने अपने-अपने कार्यो में लगकर प्रभावित लोगों की जान बचाई। एक सीएसएसआर दल ने भूकंप से प्रभावितों को निकाला। इसमें इस दल ने अप्रोच मार्ग बनाया और एक विशेष कैमरे की सहायता से मलबे में फंसे लोगों को निकाला गया। दूसरा दल सीबीआरएन ने अमोनिया गैस के रिसाव से अचेत होकर गिर जाने वाले और अन्य सैलानियों को सांस लेने में दिक्कत होने पर एक विशेष पीपी किट पहनकर प्रभावितों को निकाला गया। तीसरा फ्लड रेस्क्यू दल ने अमोनिया गैस रिसाव और भूकम्प के कारण भगदड़ मचने पर जो लोग पानी मे कुंद गए उनको बचाया गया।

इस घटनाक्रम में मुख्य भूमिका एनडीआरएफ की रही। इनके अलावा सहयोगी के तौर पर एसडीआरएफ, एनसीसी और एनएसएस के छात्रों ने भी अपनी भूमिका अदा की। इस दौरान घाट पर यंत्रो की प्रदर्शनी का भी अवलोकन कराया गया। इस प्रदर्शनी में वो सब यंत्र रखे गए जो आपदा व बचाव के कार्यो में काम आते है।

6 किमी पहाड़ चढ़ने के बाद 2 किमी में फैले गांव का किया सम्पूर्ण टीकाकरण

माही की गूंज, खरगोन।

ये कोई सैलानी पर्यटक या किसी जात्रा में जाने वाले यात्री/श्रद्धालु नहीं है। ये म.प्र. शासन की टीम है जिनके कांधों पर कोविड-19 से सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ऐसी ही टीमो के सहारे मप्र में वैक्सीनेशन महाअभियान अपनी सफलता की कहानी गढ़ रहा है। यह स्थान महेश्वर जनपद के बागोद से करीब-करीब 21 किमी. दूर देवगढ़ है। जो पूरी तरह पहाड़ियों पर स्थित है। यहां बिरले ही पहुँच पाते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र बागोद से लगभग 15 किमी. पहाड़ के नीचे बड़वी चौकी गांव है। यहां तक दो पहिया या चार पहिया वाहन से पहुँच सकते है। इसके बाद 6 किमी की कठिन पहाड़ो की चढ़ाई जिसको पैदल ही चलकर पार करना होता है। इस कठिन व दुर्गम पहाड़ी को स्वास्थ्य विभाग के दल ने एक नही कई कई बार पार किया है। सिर्फइसलिए कि यहां के पात्र नागरिको को कोविड का टीका लगाया जा सके।

महेश्वर जनपद के खंड विस्तार प्रशिक्षक जगदीश खेड़ेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि, 21 किमी. पैदल पहाड़ चढ़ने वाली टीम ने देवगढ़ को कोविड-19 से सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान की है। टीम में डॉ. बादल ओसारी, स्टॉप नर्स ललिता डावर व रंजीता यादव, वेरिफायर जय और दो आशा कार्यकर्ता ने 21 दिसंबर को आखरी बार देवगढ़ पहुंचकर सम्पूर्ण सुरक्षा का कवच दिया है। इन्होंने ने 545 की जनसंख्या वाले गांव में 362 पात्र व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक है सभी को टीका लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

युवा उत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक गतिविधियों का हुआ आयोजन

माही की गूंज, खरगोन।

पीजी कॉलेज में युवा उत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन बुधवार को नृत्य, गायन, वादन और नाटक जैसी विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. डीडी महाजन, वरिष्ट प्राध्यापक डॉ. आरएस देवड़ा, युवा उत्सव प्रभारी डॉ. डीएस बामनिया और डॉ. पुष्पा पटौदे ने माँ सरस्वती की पुष्प वंदना की और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। एकल वादन में रश्मि शुक्ला (एमएससी प्राणीशास्त्र) को प्रथम स्थान, एकल गायन (सुगम) में यामिनी पटेल (बीए तृतीय वर्ष) को प्रथम स्थान, एकल गायन (शास्त्रीय) में राहुल राठौड़ (बीकॉम तृतीय वर्ष) को प्रथम स्थान और मिमिक्री में शरद हिरवे (एमएससी गणित) को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

समूह गायन में संवेदना पंढाने समूह ने प्रथम स्थान, समूह नृत्य में संवेदना पंढाने समूह ने प्रथम स्थान और स्किट में अनिल सोलंकी समूह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विकास देवले एवं सावन धनगर समूह द्वारा कोरोना जागरूकता पर प्रस्तुत नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। साहित्यिक और सांस्कृतिक विधाओं में विजेता सभी विद्यार्थी अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पीजी कॉलेज का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. रंजीता पाटीदार ने और आभार डॉ. डीएस बामनिया ने व्यक्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार से समस्त स्टाफऔर छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

सुशासन दिवस पर अधिकारी, कर्मचारियों को दिलाई जाएगी शपथ

माही की गूंज, बड़वानी।

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदण्डों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए प्रत्येक वर्ष उनके जन्म दिवस 25 दिसम्बर के एक दिवस पूर्व सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में 24 दिसम्बर को सभी शासकीय कार्यालयों में सुशासन दिवस के अवसर पर शासकीय सेवकों को सुशासन की शपथ दिलाई जाएगी।

क्षेत्र की 9 पंचायतों के अभ्यर्थियों ने जमा किए नामांकन

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के तहत सोमवार को नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तारीख थी सारंगी पंचायत भवन पर क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायत सारंगी, छोटा बोलासा, बैंगनबड़ी, मांडन, मठ मठ, हनुमंत्या, कसारबड़ी, गामडी, मोहनपुरा पंचायतों के अभ्यर्थियों ने पंच सरपंच के लिए फार्म जमा किए।

फार्म जमा करने की अंतिम तारीख होने से जिन लोगों को टोकन वितरित किए गए थे उन्होंने देर शाम तक अपना फार्म जमा किया संवाददाता को सहायक रिटर्न अधिकारी जेएस बिष्ट वेस्ट ने बताया, ग्राम पंचायत सारंगी में 20 वार्ड हैं पंच के लिए 4 वार्ड ओबीसी के छोड़कर कुल 16 वार्ड के नामांकन पत्र जमा किए गए वार्ड वाइज स्थिति इस प्रकार है

सरपंच पद के 7 महिलाओं ने नामांकन जमा किए

वार्ड नंबर 1 अनारक्षित पुरुष के लिए 6 प्रत्याशियों ने फार्म जमा किए, वार्ड नंबर 2 से तीन प्रत्याशी , वार्ड नंबर 3 से चार प्रत्याशी , वार्ड नंबर 5 से दो प्रत्याशी , वार्ड नंबर 6 से दो प्रत्याशी , वार्ड नंबर 7 से तीन प्रत्याशी , वार्ड नंबर 8 से 4 प्रत्याशी , वार्ड नंबर 9 से तीन प्रत्याशी , वार्ड नंबर 10 से 2 प्रत्याशी , वार्ड नंबर 11 से दो प्रत्याशी , वार्ड नंबर 12 से दो प्रत्याशी , वार्ड नंबर 14 से दो प्रत्याशी , वार्ड नंबर 15 से तीन प्रत्याशी ,वार्ड नंबर 17 से 3 प्रत्याशी , वार्ड नंबर 19 से दो प्रत्याशी , वार्ड नंबर 20 से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन फार्म जमा किए।

माइनिंग विभाग द्वारा आधी रात को की गई कार्रवाई में जप्त हुए 6 डम्पर व 2 जेसीबी

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले में चल रहे सुशासन अभियान के तहत एसडीएम पानसेमल सुश्री अंशु जावला के निर्देशन में माइनिंग विभाग ने आधी रात को खेतिया के ग्राम भातकी नदी में चल रहे अवैध खनन के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की है। उक्त कार्रवाई के दौरान नदी में बण्डा एवं रेत उत्खनन, परिवहन में संलग्न 6 डम्पर एवं 2 जेसीबी को जप्त कर, खेतिया थाने की अभिरक्षा में खड़े करवाए गए है।

कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने इसी प्रकार की कार्रवाई अन्य एसडीएम को भी करवाने के निर्देश दिए है। जिससे अवैध खनन एवं परिवहन को पूरी तरह से बंद करवाया जा सके।

पंचायत निर्वाचन में जाति प्रमाण-पत्र के लिए शपथ पत्र दाखिल करने के प्रावधान

माही की गूंज, खरगोन।

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में नाम निर्देशन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र और शपथ पत्र के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी केके मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि, तृतीय चरण के लिए 30 दिसंबर से नाम निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यदि ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है कि, किसी अभ्यर्थी ने जाति प्रमाण-पत्र के लिए शपथ पत्र दाखिल किया है। दाखिल शपथ पत्र में असत्य जानकारी पायी जाती है तो भारतीय दंड विधान की धारा- 193, 415 और 419 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई के प्रावधान है। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में जाति प्रमाण-पत्र व शपथ प्रस्तुत करने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के तत्कालीन उप सचिव दिपक सक्सेना द्वारा निर्देशित किया गया है।

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव दिपक सक्सेना ने पत्र जारी किया है। 5 दिसंबर 2014 को जारी पत्र के अनुसार यदि मतदान तारीख के पहले रिटर्निंग ऑफिसर को यह ज्ञात होता है कि, कोई अभ्यर्थी जो प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं है। नाम निर्देशन पत्र में किसी ऐसे स्थान के लिए चुंकि आपत्ति न किए जाने या किसी अन्य कारण से स्वीकृत हो गया है जो यथास्थिति एससी, एसटी या ओबीसी के लिए आरक्षित है तो तत्काल ऐसे अभ्यर्थी को सूचना जारी करेगा कि, वह उस वर्ग का सदस्य होने के बाबद जिसके लिए स्थान आरक्षित है शपथ पत्र दाखिल करें। अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र दाखिल कर देता है तो रिटर्निंग ऑफिसर मामले में आगे जांच नहीं करेगा और नाम निर्देशन पत्र वैध मानेगा।

जनपद वार्ड 18 से पाटीदार को भाजपा समर्थक प्रत्याशी घोषित किया

माही की गूंज ,सारंगी।

भारतीय जनता पार्टी मंडल सारंगी में जनपद पंचायत के सामान्य वार्ड 18 से पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की भाजपा कार्यालय पर बैठक कर विचार विमर्श के बाद सर्व सहमति से ओर दोनों प्रत्याशी ने भी अपना समर्थन देते हुए रमेश रावटीया को भारतीय जनता पार्टी का समर्थक प्रत्याशी घोषित किया गया, घोषणा के पश्चात जनपद प्रत्याशी पाटीदार को बधाई और शुभकामनाएं दी।

पांच प्रकरणों के अरोपियों पर 7 हजार 500 रूपए का ईनाम घोषित

माही की गूंज, खरगौन।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने पांच प्रकरणों के अलग-अलग घटनाओं के फरार आरोपियों पर 7 हजार 500 रूपये का ईनाम घोषित किया है। फरार आरोपी सूरज मानकर पिता दिलीप मानकर निवासी ऊन का थाना ऊन में अपराध क्रमांक 348/2021 की धारा 362 भादवि, संदेही सायबा पिता नंदराम निवासी खेरदा थाना भीकनगांव में अपराध क्रमांक 11/2021 की धारा 363 भादवि और गोतम पिता मांगीलाल मानकर निवासी ऊन का थाना ऊन में अपराध क्रमांक 349/2021 की धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। इन तीन फरार आरोपियों पर 2-2 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया है। इसी तरह 39 वर्षीय गोपाल पिता सौभागसिंह सिकलीगर निवासी सतीपुरा भगवानपुरा का थाना बलकवाड़ा में अपराध क्रमांक 263/2021 की धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट तहत पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकरण के फरार आरोपी परी एक हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है। एक अन्य प्रकरण के फरार आरोपी रोकेष पिता झबरिया निवासी दसनावल बड़ा टाण्डा थाना गोगांव का थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 22/2021 की धारा 294, 323, 506, 324 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया। इस प्रकरण के फरार आरोपी परी 500 रूपये का ईनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक श्री चौधरी ने इन प्रकरणों के फरार आरोपियों की धरपकड़ या बंधी बनाने में पुलिस का सहयोग करने वाले का घोषित ईनाम दिया जाएगा। जानकारी या सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियो की लापरवाही के कारण लगातार वसुली की खबरे आ रही सामने

वक्त रहते करते कार्रवाई तो नहीं करना पड़ता निलंबन, सैकड़ों शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्यवाही के कारण होती है वसुली

माही की गूंज , पेटलावद।

सिविल हॉस्पिटल पेटलावद में अच्छे इलाज के नाम पर वसुली का खेल लगातार जारी है, गूंज द्वारा लगातार सिविल हॉस्पिटल में कार्य कर रही नर्सो द्वारा मरीज़ों से इलाज के नाम पर वसुली करने के मामले उजागर किये थे, मामले की शिकायत भी हुई लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीयो ने केवल नोटिस निकाल कर मामले को रफ़ा-दफा कर दिया जिससे सिविल हॉस्पिटल में कार्य करने वाली नर्स और डॉक्टरों की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रहीं थी। गत दिनों ऐसा एक ओर मामला सामने आया जहाॅ प्रसूता के परिवार से ड्यूटी पर रही नर्स ओर स्वीपर ने इलाज के नाम पर पैसे लिये मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की और से नर्स ओर स्वीपर पर कार्यवाही भी की गई ।

समय रहते होती कार्रवाई तो नहीं उठानी पड़ती विभाग की बदनामी

लगातार वसुली की शिकायत ओर ड्यूटी के डॉक्टरों के अनुपस्थिति होने के समाचार मय फ़ोटो के प्रकाशित किये गए लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय रहते अपने स्टाफ पर कोई नियंत्रण नही किया नतीजन सरकारी अस्पताल में अवैध रूप से हो रही वसुली जारी रही , हालांकि वसुली की गाज केवल निचले स्तर के कर्मचारी पर गिरी है लेकिन वसुली के दौरान ड्यूटी पर रहे डॉक्टरों की भूमिका की भी जांच होनी क्योंकि बिना डॉक्टर की जानकारी के नर्स लगातार पैसे मरीज़ों से वसूल रही है । बीएमओ एम एल चोपड़ा का कहना है कि इस प्रकार की शिकायतो पर हम लगातार कार्यवाही कर रहे हैं , ड्यूटी के दौरान लापरवाही करने वाले डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है ।

स्वच्छ भारत अभियान को मुंह चिढ़ाती नगर पालिका, अवैध निर्माण पर नहीं लग रही रोक

कैसे बनेगी नगरपालिका स्वच्छता की रेकिंग में नंबर वन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

नगर पालिका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के सपने को मुह चिढ़ाती नजर आ रही है। बता दे कि, अलीराजपुर नगर पालिका की निर्माण शाखा द्वारा नगर मे अवैध निर्माण की मंजूरी मौखिक रुप से दे रखी है। मगर लिखित मंजूरी नही है। बगैर मंजूरी के नगर मे बेखोफ अवैध निर्माण हो रहे है और जिन मकानों के निर्माण की अनुमति जारी भी की गई है, तो वह भी अपने स्वामित्व क्षेत्र से बाहर अवैध निर्माण कर रहे है जिसपर भी नगरपालिका को ध्यान देना होगा। कही मकानों के निर्माण मे गलियों मे भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है, ओटले बनाने से नालियों की साफ-सफाई नही हो पा रही है। जिस पर रोक लगाने मे निर्माण शाखा फैल हो रही है। जिसके चलते घरों का मलबा व मटेरियल, रैत, गिट्टी, इटे नगर की नाली मे फेक रहे है जिससे नालियाँ जाम हो रही है। ऐसे हालत मे नगर पालिका अलीराजपुर स्वक्छ्ता की रैंकिंग से दूर-दूर तक नजर नही आ रही है।

माहमारी मे नगर मे गंदगी फैलाने मे नगर पालिका खुद जिम्मेदार है। लगातार खबरें प्रकाशित करने पर भी निर्माण शाखा द्वारा कोई कार्रवाई न करना समझ के परे है। जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन मे भी की जा चुकी है। नगर मे अवैध निर्माण जोरो पर चल रहे है।

बता दे कि, बस स्टेशन पर अवैध कॉम्पलेक्स मे बनी दुकाने जो बगैर मंजूरी के बनाई गई थी जो नगर पालिका के मात्र 100 मिटर की दुरी पर है जिसकी शिकायत के बाद भी दुकानो का अवैध निर्माण हुआ है। जिसको तोडने का आदेश आने के बाद भी नगर पालिका मौन है।

आगामी पंचायत चुनाव, त्यौहार एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु अपराध समीक्षा मीटिंग का आयोजन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

पुलिस नियंत्रण कक्ष अलीराजपुर में समस्त राजपत्रित अधिकारी पुलिस एवं थाना प्रभारियों की बैठक एसपी द्वारा ली गई। आयोजित क्राईम मीटिंग में प्रत्येक थाना प्रभारी से रूबरू चर्चा कर वर्ष 2021 की समाप्ति के पूर्व चिन्हित अपराध, समस्त लंबित अपराध, चालान, मर्ग, शिकायतें एवं अन्य समस्त प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए तथा प्रकरण सदर में आ रही कठिनाईयों को सूना व उसके निराकरण हेतु आवश्यक सुझाव देकर निराकरण हेतु समझाईश दि गई। मीटिंग में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीतिक चर्चा कर क्रिटीकल मतदान केन्द्रों का चिन्हाकन, नाकेबंदी, रोड पेटोलिंग को लेकर चर्चा की गई। आगामी क्रिसमस त्यौहार को शांतिपूर्व मनाये जानें को लेकर पुख्ता पुलिस इंतजाम लगानें के निर्देश दिए। साथ ही समस्त अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि, असामाजिक तत्वों एवं सौहाद्रपूर्ण वातावरण को बिगाडनें वालें तत्वों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें तथा किसी भी स्तर पर ऐसे असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाए।

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि, पुलिस की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना है तथा थानाक्षेत्र में गंभीर अपराध किसी भी स्तर पर घटित न होनें पाए। इस हेतु कार्ययोजना के तहत प्रतिदिन प्रभावी कार्रवाई करें, जिससे समाज में भयमुक्त वातावरण बना रहे।

अवैधरूप से रेत परिवहन के विरूद्ध पुलिस ने की कार्रवाई

माही की गूंज, अलीराजपुर।

एसपी मनोज कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि, अवैध रूप से रेत परिवहन कर शासन के राजस्व का नुकसान करनें वालों की लगातार शिकायतें मिल रही थी। जिस पर अलीराजपुर पुलिस के द्वारा निगाह रखी गई तथा रेत परिवहन मार्ग के थानों को इनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के स्पष्ट निर्देश दिए गए। इसी के तारतम्य में अलीराजपुर पुलिस के द्वारा तीन थानों क्षैत्रों में अवैध रेत परिवहन करनें पर कार्यवाही की गई है। कुल 5 अपराध पंजीबद्ध किए गए है, जिसमें थाना सोरवा में 2, चांदपुर में एक एवं कोतवाली में 2 अपराध हैं। उक्त दर्ज अपराधों में 5 डम्फर कुल कीमती करीबन 75 लाख रुपए, 2 ट्राले कीमती करीबन 20 लाख रुपए है। इस प्रकार कुल 5 अपराधों में 7 वाहन जप्त किए जाकर करीबन 95 लाख रुपए के वाहन जप्त की कार्रवाई की गई है। उपरोक्त 05 प्रकरणों में जप्त 7 वाहनों के राजसात की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारी को भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि, अलीराजपुर पुलिस के द्वारा अवैध व्यवसाय करने वालों के विरूद्ध लगातार सूक्ष्मता से नजर बनाए हुए हैं तथा अवैध गतिविधियों में लिप्त किसी भी स्तर पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इनके विरूद्ध अलीराजपुर पुलिस की लगातार प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

जिले की सीमा क्षेत्र में धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए उसकी रोकथाम एवं संक्रमण से सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि, विभिन्न गतिविधियों को इस प्रकार से विनियमित किया जाए जिससे कारोना के नए वेरियंट से संक्रमण न फैल सकें। उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में जन सामान्य की सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य, लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।

जिले में कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस का प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाए बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने हेतु पूर्णरूपेण से प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त शासकीय/अशासकीय बैंक, स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों, कोचिंग क्लासेस, संचालक, स्टाफ छात्र-छात्राओं तथा समस्त मार्केट प्लेस के प्रतिष्ठान एवं मॉल, जिम, सिनेमाघर में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों के पास टीकाकरण का प्रमाण होना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति के अपने मोबाईल में टीकाकरण प्रमाण-पत्र होने पर वह मान्य होगा। जिले में संचालित सभी शासकीय/अशासकीय कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों के पास कोरोना टीकाकरण द्वितीय डोज का प्रमाण होना आवश्यक होगा।

साथ ही इन संस्थाओं में उपस्थित होने वाले आम व्यक्ति के पास भी टीकाकरण का प्रमाण होना अनिवार्य है। वैक्सिनेशन लगाए बिना सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश वर्जित होगा तथा तत्संबंधी जॉच आकस्मिक रूप से कभी-भी की जा सकती है।

उपरोक्त बिन्दुओं का पालन कराना सभी कार्यालय प्रमुख प्रतिष्ठान संचालक का उत्तरदायित्व रहेगा। जिले में संचालित होने वाले साप्ताहिक हाट-बाजारों में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों का कोरोना टीकाकरण का प्रथम एवं द्वितीय डोज का प्रमाण दिखाया जाना अनिवार्य होगा। जिले में कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा।

चूँकि यह आदेश जन साधारण पर लागू है तथा परिस्थितिवंश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि, जन सामान्य पर उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की

धारा 144 (5) के अन्तर्गत अयोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अयोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू प्रतिबंध से छूट दे सकेगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

धर्मनिस्ट सुश्रावक श्री बडोला का संथारा सहित देवलोक हुए

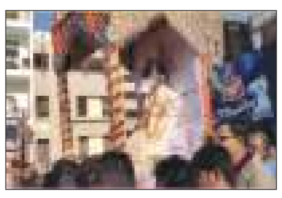

माही की गूंज,मेघनगर। पत्रकार पंकज बडोला और संजय बड़ौला के पिता श्री सुश्रावक बसंती लाल जी बड़ौला का मंगलवार शाम अंतिम मनोरथ संथारा परम पूज्य श्री दिलीप मुनि जी महाराज साहब के द्वारा किया गया। अंतिम समय में नवकार मंत्र के जाप स्तवन आलोचना आदि श्रवण करते हुए देवलोक गमन हुए। अंतिम यात्रा में बुधवार को सुबह ढोल के साथ नगर के समाज जन और नगर मे बस स्टैंड पर काफी संख्या में एकत्रित हुए और अंतिम यात्रा में बस स्टैंड से होते हुए ऑयल मिल भंडारी चौराहा झाबुआ चौराहे होते हुए मुक्तिधाम पहुंची। जहा श्री बडोला को अंतिम मुखाग्नि दी गई।

असमंजस्य के बीच गहमा-गहमी शुरू

माही की गूंज खवासा। कोर्ट के आदेश के बाद सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव टलने की आशंका के बावजूद फार्म भरने के समय संभावित उम्मीदवारों में गहमा गहमी रही। अंतिम दिवस में बड़ी संख्या में दावेदारों ने लाइन में लगकर अपने फार्म जमा किए। आज सबकी निगाहें नाम वापसी पर टिकी है वोटों के जोड़-घटाव के साथ ही संभावित उम्मीदवार किसी को वोट कटने के फायदे गिन रहा है, तो कोई किसी उम्मीदवार को अपनी राह में रोड़ा मानकर समझा बुझा रहा है। बहरहाल आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी और दावेदारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सभी के मन में एक सवाल अवश्य है कि, क्या चुनाव अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे...? कई सरपंच पदों के दावेदारों का कहना है कि, अगर चुनाव आगे बढ़ते हैं तो, उनका खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि प्रचार में जितना कम समय रहेगा उतना ही कम खर्चा दावेदारों का होना है। वहीं कुछ सरपंच पद के दावेदार अपने समर्थित पंच को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, ताकि आगे उप सरपंच सहित अन्य कार्यों में उन्हें अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़े।

जहां तक ग्राम पंचायत खवासा का सवाल है यहां 7 दावेदार सरपंच के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वही पाटडी में 8, रत्नाली में 9, चापानेर में 8, देवगढ़ में 5 तथा सागवा में 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं वार्ड वार अगर देखें तो खवासा के 20 वार्ड में से 3 वार्ड ओबीसी के होने से नामाकन नही लिए बचे 17 वार्ड मे 33 नामांकन, पाटड़ी के 15 वार्ड में 18, रत्नाली के 11 वार्ड में 24 , चापानेर के 17 वार्ड में से 3 वार्ड मे किसी ने भी नामांकन नही भरा बाकी 14 वार्ड में 17, देवगढ़ के 11 वार्ड में से 2 वार्ड मे नामांकन किसी ने नही भरे बचे 9 वार्ड के लिए 11 तथा सागवा के 12 वार्ड में 13 दावेदारों ने अपने फार्म भरे हैं। 3 वार्ड ओबीसी के कारण नामांकन नही लिये वही 5 वार्ड से फार्म नामांकन नही भरे है इस तरह कुल 8 वार्ड रिक्त है इस प्रकार खवासा सेक्टर की कुल 6 पंचायतो मे सरपंच हेतु 43 व पंच के लिए 116 दावेदार है। सभी दावेदारो के फार्म स्वीकृत किये गए सिर्फपाटडी मे सरपंच पद हेतु एक ही उम्मीद्वार ने अपने नाम से 2 नामांकन फार्म भरे थे जिसमे से पहला फार्म स्वीकार कर द्वितीय फार्म अस्वीकार किया गया।

निझर्रणी महोत्सव भक्तिमति शबरी लीला नाट्य ने दर्शकों का मन मोहा

विभिन्न जिलों के कलाकारों ने दी नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां

माही की गूंज, अलीराजपुर।

मध्यप्रदेश शासन संस्ति विभाग द्वारा जिला प्रशासन अलीराजपुर के सहयोग और समन्वय से तीन दिवसीय निझर्रणी महोत्सव का आयोजन अलीराजपुर में किया जा रहा है। 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव तथा नदियों के प्रति धन्यता प्रकट करने और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृति को समपिर्त निझर्रणी महोत्सव के दूसरे दिन जनजातीय नृत्य भगोरिया एवं निमाड़ लोकनृत्य गणगौर की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा दी गई। दूसरी प्रस्तुति वनवासी लीला नाट्य भक्तिमति शबरी को उड़ीसा की पारम्परिक रामलीला मंचन शैली जात्रा को आधुनिक तकनीकि माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस लीला नाट्य का निर्देशन गुरू निमर्लदास द्वारा एवं आलेख योगेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। लीला की विशिष्टता यह है कि, इनके अभिनय से सम्बद्ध कलाकार प्रदेश के अलग-अलग जनजातीय और लोक समुदाय से हैं। रामकथा साहित्य में शबरी भक्ति के पयार्य के रूप में बहुत प्रमुखता से वणिर्त की गई है। मनमोहक लाइट्स, सुमधुर साउंड इफैक्ट के साथ प्रारंभ हुई उक्त लीला नाट्य की शुरूआत भगवान श्रीराम की आरती से हुई। आगे के दृश्य में बताया कि, पिछले जन्म में माता शबरी एक रानी थीं, जो भक्ति करना चाहती थीं, लेकिन माता शबरी को राजा भक्ति करने से मना कर देते हैं। तब शबरी मां गंगा से अगले जन्म भक्ति करने की बात कहकर गंगा में डूब कर अपने प्राण त्याग देती हैं।

अगले दृश्य में शबरी का दूसरा जन्म होता है और गंगा किनारे गिरि वन में बसे भील समुदाय को शबरी गंगा से मिलती हैं। भील समुदाय् शबरी का लालन-पालन करते हैं और शबरी युवावस्था में आती हैं तो उनका विवाह करने का प्रयोजन किया जाता है लेकिन अपने विवाह में जानवरों की बलि देने का विरोध करते हुए वे घर छोड़ कर घूमते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचती हैं, जहां ऋषि मतंग माता शबरी को दीक्षा देते हैं। आश्रम में कई कपि भी रहते हैं जो माता शबरी का अपमान करते हैं। अत्यधिक वृद्धावस्था होने के कारण मतंग ऋषि माता शबरी से कहते हैं कि, इस जन्म में मुझे तो भगवान राम के दशर्न नहीं हुए लेकिन तुम जरूर इंतजार करना भगवान जरूर दशर्न देंगे।

लीला के अगले दृश्य में गिद्धराज मिलापए भगवान राम एवं माता शबरी मिलाप प्रसंग मंचित किए गए। भगवान राम एवं माता शबरी मिलाप प्रसंग में भगवान राम माता शबरी को नवधा भक्ति कथा सुनाते हैं और शबरी उन्हें माता सीता तक पहुंचने वाले मार्ग के बारे में बताती हैं। लीला नाट्य के अगले दृश्य में शबरी समाधि ले लेती हैं। उक्त पूरी नाट्य प्रस्तुति को बढे ही मधुर और बढे ही साउंड और चित्र इफैक्ट के साथ कलाकारों द्वारा जीवंत प्रस्तुति दीए जिसने भी उक्त प्रस्तुति को देखा वह मंत्र मुग्ध हो गया। निझर्रणी महोत्सव को देखने बडी संख्या में आमजन कडाके की ठंड के बावजूद पूरे समय कायर्क्रम स्थल पर उपस्थित रहे। उन्होंने प्रत्येक प्रस्तुतियों पर कलाकारों का तालियां बजाकर सम्मान किया।

बोहरा समाज ने पैदल गलियाकोट तीर्थ पहुँचकर मिन्नते की

माही की गूंज, आम्बुआ।

बोहरा समाज के धर्मगुरु डॉ. सैय्यदना मुफ़्फ़दल सैफुद्दीन सा. की लंबी उम्र हेतु जहाँ पूरे विश्व मे कामना की जा रही है वही आम्बुआ जैसे एक छोटे से कस्बे के लगभग 45 समाजजनों द्वारा प्रसिद्ध तीर्थ फतेहपुरा से गलियाकोट 45 किलोमीटर पैदल चलकर उनकी लंबी उम्र हेतु प्राथना की गई। वही समाज के वरिष्ठ शब्बीर भाई ने बताया कि, पिछले 2 वर्षों से आम्बुआ बोहरा समाज के लोग फतेहपुरा से गलियाकोट 45 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर धर्मगुरु डॉ. सैय्यदना सा. के शुभ कदम आम्बुआ में रखवाना चाहते है इसको लेकर महिलाए भी इस वर्ष पैदल चल कर मन्नते मांगी।

किटनाषक पिने से मौत

माही की गूंज,थांदला। ग्राम इटावा में 2 वर्ष पूर्व प्रेम प्रसंग के तहत विवाह करने वाली 20 वर्षीय युवती ने ससुराल में कीटनाशक पी लिया। मंगलवार को परिजन महिला को गंभीर हालत में स्थानीय चिकित्सालय लाए जहां देर रात महिला की मौत हो गई थाना प्रभारी कौशल्या चौहान ने बताया कि, मृतिका शांति पति रूपा सिंगारडिया निवासी इटावा ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, महिला के ससुराल पक्ष से उसे मंगलवार को गंभीर हालत में उपचार हेतु लाए थे जहां महिला की मौत हो गई।

सूचना

मेरा नाम विशाल कनेश पिता श्री धनसिंग कनेश गाँव पुवासा, पोस्ट सिलोटा तहसील सोंडवा जिला अलीराजपुर का निवासी हुं। मेरा बेग बस में से किसी ने उतार लिया था। उसमें मेरे जरूरी डॉक्युमेंट थे। जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 10 वी कक्षा की स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ओर अन्य सामान भी था। जिस किसी को भी पता चले तो मुझे मेरे मोबाईल न. 9753770052 पर सम्पर्क करें

'पताः- गांव पुवासा, पोस्ट सिलोटा तहसील सोंडवा जिला अलीराजपुर (म.प्र.)'

अगर प्रशासन सही और बॉयो डिजल का कारोबार अवैध है तो फिर माफियाओ के ठिकानें क्यों नहीं उखाड़ फैकता प्रशासन

डीजल माफियाओं के ढीले पड़े तेवर या प्रशासन अपनी लुटती इज्जत बचाने का कर रहा प्रयास

जिले के सारे अवैध डीजल माफियाओं के ठीकाने सील, मगर रामपाल का चल रहा जादू

पिटोल से हकाले गए युसूफ ने देवझिरी में फिर जीजे3 ढाबे को बनाया अपना अड्डा

अंतरवेलिया स्थित झूठे माफिया पंडित का जयदीप बायो फ्यूल पंप खबरें प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने किया सील।

छापरी स्थित रामपालसिंह चौहान का यह अवैध डीजल पंप अब भी अदृश्य शक्ति के चलते हो रहा है संचालित।

खजूरखो वाले अवैध डीजल के ठीकानें को भी किया गया सील, मगर माफियाओं की निगराने के लिए पुलिस जवान तैनात।

माही की गूंज टीम के साथ संजय भटेवरा की रिर्पोट

झाबुआ।

"बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है,
हर शाख पे उल्लू बैठें हैं अंजाम ऐ गुलिस्तां क्या होगा।"

मशहूर शायर शौक़ बहराइची का यह शेर इन दिनों जिले की परिस्थितियों पर सटीक बैठता नजर आ रहा है। जिस तरह से माही की गूंज ने अवैध डीजल माफियाओं के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है, उससे डीजल माफिया और सारा का सारा प्रशासनिक अमला सकते में है। जिले में चल रहे इन अवैध डीजल पंपों के माफियाई मालिकों की बौखलाहट के कारण कभी प्रशासन सील कर देता तो कभी इन्हे खुली छूट दे देता। सील करने, बंद करने और खोलने का यह खेल प्रशासन को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर रहा है। प्रशासन यह जानता है कि, जिले में इन अवैध डीजल माफियाओं का मकडज़ाल फैला हुआ है। बावजूद इसके सिर्फ दिखावे की कार्रवाई अब तक की जाती रही है। कार्रवाई के नाम पर अवैध डीजल माफियाओं के पंपों को सील कर छोड़ दिया जाता और कुछ समय बाद पर्दे के पीछे से इशारा मिलते ही यह माफिया फिर से सक्रिय हो जाते और अपना काले तेल का गौरख धंधा फिर से शुरू कर लेते है। प्रश्न यह कि, यदि प्रशासन यह मानकर कार्रवाई करता है कि जिले में बॉयो डीजल के नाम पर चल रहे यह डीजल पंप अवैध है तो फिर इन्हे पूरी तरह से बंद कर माफियाओं के विरूद्ध अपराधिक मामला दर्ज कर तामझाम क्यों नहीं उखाड़कर फैक देता...?

मगर दल्ले बन चुके प्रशासन की यह भी एक मजबूरी कि, यदि पूरी तरह से इन माफियाओं के ठीकानों को बंद कर दिया जाए तो साहब लोगों की जेबे कहां से गर्म हो। अधिनस्थों की मजबूरी यह कि, साहब की इजाजत के बगैर पत्ता तक नहीं हिला सकते तो माफियाओं पर कार्रवाई तो दूर की कोड़ी है। मतलब जैसा आदेश वैसा काम, मगर ऐसा भी नहीं है कि, अपने उच्चाधिकारियों के इशारे पर नाचते हुए अधिनस्थों के हाथ कुछ नहीं लगता। जिलाधिकारियों द्वारा दूध से भरी तपेली को साफ करने के बाद उसमें जमी मलाई की खुरचल तो अधिनस्थों के हाथ लग ही जाती है। वैसे भी झूठन खाने की आदत इस जिले के अधिकारियों को बहुत पहले से है। साहब लोगों को खिलाने के बाद दंभ भिड़ते माफियाओं की फिसलती जुबान इस बात का नमूना है। हम पहले भी अपने पिछले अंकों में माफियाओं द्वारा जिला अधिकरियों की मांग भरने और अधिनस्थों के मुंह में चांदी के चम्मच ठूंसने की कहानी लिख चुके है। अधिकारियों व अधिनस्थों के इस खेल को देखते हुए तो यही कहा जाएगा कि,

"बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है,
हर शाख पे उल्लू बैठें हैं अंजाम ऐ गुलिस्तां क्या होगा।"

कार्रवाई महज दिखावे की कुछ भी नहीं करते जप्त

फिलहाल बॉयो डीजल के नाम पर जिले में चल रहे लगभग सभी ठीकानें प्रशासन सील कर चुका है। सील क्यों किए यह तो प्रशासन ही जाने। क्योंकि अवैध डीजल माफियाओं के यही ठीकानें प्रशासन पहले भी कई बार सील कर चुका है, सील करने के बाद अवैध डीजल माफियाओं के यह ठीकाने फिर से कैसे शुरू हो जाते है यह भी प्रशासन ही जाने। बड़ी बात यह कि, सील किए गए डीजल माफियाओं के ठीकानों से अवैध डीजल बैचने की कोई सामग्री प्रशासन आज तक जप्त नहीं कर पाया है। जैसे वाहनों में डीजल भरने की मशीन, अवैध डीजल स्टोर करने के लिए लगाए बड़े-बड़े टैंक, अवैध डीजल को परिवहन कर लाने वाले टैंकर और न यह पता किया जाता कि, जिस जमीन पर माफियाओं का यह अवैध डीजल पंप चल रहा है वह किस की जमीन है और कारोबार कोन कर रहा है और ना ही उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाती, न ही ऐसी जमीनों के कोई कागजात या लिखापढ़ी अब तक प्रशासन ने टटोली है। इस सारे घटना क्रम से समझदारों की समझ में तो यही आता है कि, दल्ला प्रशासन माफियाओं को खुली छूट और संरक्षण दे रहा है। वह दिन भी दूर नहीं जब यही सील किए गए सारे ठीकानें कुछ दिन बाद फिर से गठजोड़ के साथ चालु हो जाएंगे और स्थिति ढाक के तीन पात हो जाएगी।

प्रशासन को न जाने कौन सी घुट्टी पिलाई रामपालसिंह चौहान ने

पिछले तीन-चार दिनों में हुई कार्रवाई के बाद जिले के लगभग सारे अवैध डीजल माफियाओं के ठीकानें प्रशासन ने सील कर दिए। मगर बैतुल-अहमदाबाद हाईवे पर ग्राम छापरी में बॉयो डीजल के नाम अवैध डीजल का काला धंधा कर रहे रामपाल का पंप यथावत पूर्व की तरह अब भी चालू है, पता नहीं रामपाल ने प्रशासन को किस तरह की घुट्टी पिलाई कि, जिले के सारे माफियाओं के अवैध डीजल पंप अभी बंद है और सिर्फ रामपाल का अवैध ठीकाना चालु। सांठ-गांठ के साथ कहीं यह सत्ता और सरकार का जोर तो नहीं जिसके आगे प्रशासन "जो हुक्म मेरे आका" की तर्ज पर नतमस्तक हो गया, या फिर प्रशासन ने तमाम माफियाओं से तलाक लेते हुए सिर्फ रामपाल से ही पूरी मांग भरवा ली। अगर ऐसा है तो अब जिले में सिर्फ रामपाल ही पूरे मजे लेगा और देगा। माफिया रामपालसिंह चौहान के भाजपा और भोपाली कनेक्शन भी हम अपने पूर्व के अंकों में बता चुके है। जिले से कलसिंह भाबर के जरिए होती हुई रामपालसिंह चौहान की रस्सी भोपाली गलियारों तक पहुंचती है। रामपाल का यह भोपाली कनेक्शन हम साक्ष्यों के साथ प्रमाणित भी कर चुके है, अगर यह सही है तो फिर प्रशासन की स्थिति जिले में "रामपाल की जोरू सबकी भाभी" जैसी हो जाएगी।

युसूफ भी चला रहा मगर चोरी छिपे

इधर पिटोल से हकाला गया युसूफ फिर से अपने पुराने ठीकाने पर लौट आया है, युसूफ का कोई स्थाई ठीकाना नहीं है, यह डायरेक्ट टैंकरों से पिछले कई महीनों से अवैध डीजल की सप्लाय करता रहा है। स्थाई ठीकाना नहीं होने की वजह से यह अपना स्थान एक वेश्या की तरह बदलता रहा है। सबसे पहले इसने देवझिरी में नेशनल हाईवे के किनारे जीजे 3 ढाबे को अपना ठीकाना बनाया था। मगर यहां पर कुछ चटर गुल्ले चवन्नी छाप पत्रकारों ने इसकी नाक में इतना दम किया कि, अधिकारियों की मांग भरने और मुंह में चांदी के चम्मच ठूंसने के बावजूद उसे अपना यह ठीकाना छोडऩा पड़ा। एक ने तो युसूफ के इस अवैध धंधे का वीडियो बनाकर सीधे तौर पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा को भी दिखाई थी। कलेक्टर को वीडियो दिखाने के बावजूद युसूफ के धंधे पर उस समय कोई असर नहीं पड़ा था। यहां से हटने का दर्द युसूफ को इतना था कि, उसके गुर्गे बताते है कि, जिस जगह और जिस आदिवासी की जमीन पर हम धंधा कर रहे है, उसी का संरक्षण और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। जबकि हम उसकी जमीन का हर महीने 25 से 30 हजार भुगतान करते है और इसीलिए हमें यह जगह छोडऩे पर मजबूर होना पड़ा। यहां से ठीकाना बदलते हुए युसूफ ने पिटोल को अपनी शरणस्थली बनाया था। मगर पिटोल में धंधे में कॉम्पीटीशन बहुत ज्यादा था। जिस जगह को युसूफ ने अपना ठीकाना बनाया था उसके आगे और पीछे माफियाओं की भरमार थी। युसूफ के एक ओर मामा-भानेज ढाबे पर यह अवैध धंधा चल रहा था तो दूसरी ओर होटल सागर पर अज्जू-विज्जू ने धूम मचा रखी थी। कॉम्पीटीशन के बावजूद युसूफ अच्छा धंधा कर रहा था, अब उसके पास डीजल भरने की दो मशीने हो चुकी थी जो डायरेक्ट अवैध डीजल से भरे टैंकरों से वाहनों में डीजल भरती थी। मगर क्या करें "धंधा तो गंदा ही है" मतलब अवैध ही है। समय ने ऐसी पलटी मारी की माही की गूंज में छप रहे समाचारों के साथ पिटोल के सारे अवैध डीजल के ठीकानें बंद हो गए। कुछ दिन आराम करने के बाद जब युसूफ ने कोई हल निकलता नहीं देखा तो अपना ठीकाना बदलने का इरादा किया। इस बीच युसूफ पिटोल से लेकर माछलिया तक अपने ग्राहकों को चलित सेवा उपलब्ध कराता रहा। मतलब छोटे पीकअप टैंकर से पूरे हाईवे पर गश्त करता हुआ अपना माल खपाता रहा। जो ग्राहक जहां मिल जाता उसे वहीं मौका देखकर अवैध डीजल खपा देता, अब युसूफ फिर से अपने पुराने ठीकाने की ओर आ चुका है। उसने फिर से देवझिरी में नेशनल हाईवे पर स्थित जीजे 3 ढाबे को अपना ठीकाना बना लिया है। सुत्र बताते है कि, युसूफ अब यहीं से अपना काम-काज चला रहा है मगर दबे-छीपे, बड़े टैंकरों से माल नहीं लाया जा रहा बल्कि पिकअप पर लगे छोटे टैंकर से ही वह अपना काले तेल का गौरख धंधा चला रहा है। यह वही युसूफ है जो साहब लोगों की मांग भरने और अधिनस्थों के मुंह में चांदी के चम्मच ठूंसने का दंभ छाती ठोक कर भिड़ता था।

झूठा माफिया पंडित, अगर सारे कागजात पूरे थे तो फिर क्यों सील हो गया जयदीप पंप

जिले के अंतरवेलिया स्थित जयदीप बॉयो फ्यूल नाम से संचालित बॉयो डीजल पंप पर भी कार्रवाई हुई और इसे भी सील कर दिया गया। माही की गूंज अपनी चलाई जा रही अवैध बॉयो डीजल की सीरीज में भी इस अवैध संचालित पंप के बारे में अपने पाठकों को जानकारी दे चुका है। 25 नवंबर के अंक में छपे समाचार के बाद जयदीप बॉयो फ्यूल का संचालक मोहित पंडित इस कदर उत्तेजित हो गया कि, उसने सीधे अखबार के कार्यालय पर फोन कर धमकाने की कोशिश की। फोन पर अपने आपको एक टीवी चैनल का पत्रकार बताया, लेकिन जब माही की गूंज ने इसकी पुष्टी की तो पंडित तो बहुत बड़ा झूठा निकला। माही की गूंज प्रतिनिधि ने जब उस न्यूज चेनल के इंदौर डिवजनल हेड से बात की तो पता चला कि, हमारे द्वारा झाबुआ, मेघनगर, थांदला में इस तरह का कोई प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया गया है और अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वह गलत है। हमें उस व्यक्ति की जानकारी दें, हम उचित कार्रवाई करेंगे।

माही की गूंज कार्यालय में फोन कर के धमकाते हुए झूठा माफिया पंडित कहता है कि, आपने मेरे खिलाफ समाचार क्यों लगाया, मेरे बॉयो डीजल पंप के सभी कागजात मौजूद हैं। सिर्फ एक एनओसी नहीं थी जो मुझे आठ दिन पहले ही मिल गई है। बहस में वह यह भी बताता है कि, उसका यह पंप 2017 से संचालित हो रहा है। जब झूठे माफिया पंडित से यह सवाल किया गया कि, एनओसी तो आठ दिन पहले मिली है, इसके पहले तो यह पंप अवैध तरीके से ही संचालित हो रहा था? तो माफिया कहता है केंद्रिय गजट में लिखा है कि, सितंबर 2020 के पहले लगे बॉयो डीजल पंपों को किसी प्रकार की कोई एनओसी की आवश्यकता नहीं थी। मेरे सारे कार्य एक नंबर में कर राजस्थान के शिवम एजेंसी से बॉयो डीजल मंगवा कर प्रतिमाह दो से चार लाख रुपये का जीएसटी भरता हूं। जब गजट में सितंबर 2020 के पूर्व के लगे बॉयो पंप में अन्य किसी प्रकार की एनओसी की आवश्यकता नहीं थी तो एनओसी 8 दिन पूर्व आपको क्यों लेना पड़ी...? के जवाब में संचालक कहता है, गवर्मेंट ने कहा तो एनओसी ली गई। जबकि झूठा माफिया पंडित जितनी जीएसटी भरने का हवाला दे रहा है उससे यह साफ होता है कि, एक माह में उसके डीजल पंप से अधिकतम 30 हजार लीटर ही बॉयो डीजल खपत होता है। जबकि जिले में बॉयो डीजल के नाम पर चल रहे इन अवैध डीजल माफिय्राओं के प्रत्येक ठीकाने से प्रतिदिन 10 से 15 हजार लीटर डीजल की खपत होता है। अब बाकी का डीजल पंडित कहां से और कैसे लाता है यह विचारणीय ही नहीं बल्कि संदेहहास्पद भी है। झूठे पंडित के अवैध डीजल पंप पर गुजरात नंबर के टैंकर अवैध डीजल लेकर आते है और खाली होते देखे भी गए है। जिनकी फोटो और वीडियो माही की गूंज के पास उपलब्ध है।

जयदीप बॉयो फ्यूल के संचालक की गोलमोल व दवाब पुर्ण बातों के बाद जब हमने कहा कि, कलेक्टर ने एनओसी जारी की है और आप एक नंबर का कार्य कर रहे हो तो हम आपके पक्ष में खड़े रहेंगे, लेकिन जो एनओसी कलेक्टर ने जारी की है वह बता दे। जिस पर अपने आपको पत्रकार कहने वाला झूठा पंडित बौखलाने लगा और कहने लगा, मैं तुमको सिर्फ यह बता सकता हूं की एनओसी मिल चुकी है, पर मैं तुम्हें एनओसी नहीं दिखाऊंगा, मैं पंडित हूं और मैं किसी भी अधिकारी के मुंह में चांदी की चम्मच नहीं ठुसता हूं। इस संबंध में पूरी कहानी हम अपने पिछले अंक में प्रकाशित कर चुके है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि, बड़ी-बड़ी डींगे हाकने वाले डीजल माफिया झूठे पंडित के सारे दावों की हवा निकल चुकी है। पूरे कागजात होने का दावा करने वाले झूठे पंडित माफिया का पंप भी प्रशासन ने माही की गूंज में झूठे पंडित के सम्बध में उसके मोबाईल नम्बर के साथ समाचार प्रकाशित होने के बाद सील कर दिया है। अब यह कब तक सील रहेगा या दौबारा कब चालू होगा यह तो प्रशासन जाने या झूठा माफिया पंडित। मगर माही की गूंज अपने संकल्प "बेबाकी के साथ सच" को साकार करता रहेगा।

युसूफ ने फिर जीजे 3 ढाबे को बनाया अपना ठीकाना चोरी-छीपे पीकअप टेंकरों से वाहनों में भरता है अवैध डीजल।

लगभग जिले के सभी अवैध डीजल माफियाओं के पास गुजरात पासिंग टेंकर मौजूद है जिसमें वे अवैध डीजल का परिवहन करते है।

बकायदा इन अवैध संचालित टेंकरों पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिखा हुआ है और नामी कंपनियों के होलोग्राम भी प्रिंट है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422